Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 81
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.0
रविवार, 29 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 राज्य में पाइप से प्राकृतिक गैस वितरण की ...

4 नौकरी की दौड़ में खोती शिक्षा...

7 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका,...

संक्षिप्त न्यूज

बिहार के विद्यालयों में 'वंदे मातरम्' अनिवार्य, सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

पटना। बिहार में सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान सप्ताह में कम से कम एक बार 'वंदे मातरम्' गाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र के निर्देशों के अनुरूप जारी इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को सुदृढ़ करना और विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। नए निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में सुबह की सभाओं में 'वंदे मातरम्' को शामिल किया जाएगा। इसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश

दिए गए हैं और संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके साथ ही राष्ट्रीय पर्वों, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य आधिकारिक अवसरों पर भी इस गीत का गायन अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य शैक्षणिक और सार्वजनिक संस्थानों में राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ी परंपराओं को व्यवस्थित करना है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान के दौरान सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक खड़ा होना आवश्यक है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनादर को गंभीरता से लिया जाएगा।

हालांकि, यह भी कहा गया है कि चलचित्र या समाचार प्रसारण के दौरान राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। यह निर्णय सार्वजनिक संस्थानों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

पीएम मोदी की विपक्ष को कड़ी चेतावनी-

पश्चिमी एशिया संकट पर राजनीति न करें, देश माफ नहीं करेगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पश्चिमी एशिया में एक महीने से युद्ध जारी है और भारत देशवासियों के भरोसे के साथ इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। मोदी ने वैश्विक संकट की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, 'मैं प्रदेश व देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकट से ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक है।' उन्होंने कहा, 'जो भारतीयों और भारत के हक में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति हैं। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में कुछ नंबर पाएंगे लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। 'प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण समेत कार्गो हब का उद्घाटन करने के बाद जेवर में एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'आज पूरा विश्व चिंतित हैं, पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध जारी है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने-पीने के सामान, डीजल, खाद का संकट सामने आया है।' मोदी ने कहा, 'हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है लेकिन भारत देशवासियों की ताकत के भरोसे इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है।' उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल व गैस प्रभावित देशों से मंगाता है इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है

जिससे सामान्य परिवारों, किसान भाई-बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा, 'विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। यह आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध जारी है, उससे उपजे संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी बताया है। मेरी कल (शुक्रवार को) सभी मुख्यमंत्रियों से लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई है।' मोदी ने कहा, 'आज जनता से फिर से कहूंगा कि हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुलकर इस संकट का सामना करना है। यह पूरे विश्व में परेशानी करने वाला संकट है और हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है।

यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है।' प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों को आगाह करने के साथ-साथ कहा कि कोरोना के संकट में कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर झूठ बोला, अफवाहें फैलाई ताकि सरकार का काम कठिन हो, देश को नुकसान हो लेकिन परिणाम क्या हुआ। मोदी ने कहा, 'जनता ने चुनाव के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल इससे सबक सीखेंगे और देश को ताकत देंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर से शानदार हवाई अड्डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मोदी ने हवाई अड्डे के महत्व को समझाते हुए कहा, 'आज हम विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले राज्यों में एक बन गया है।'

उन्होंने कहा, 'यह हवाई अड्डा नोएडा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, समेत कई जिलों को लाभ देने वाला है। प्रदेश के किसानों, लघु उद्योगों और नौजवानों के लिए अनेक अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, यह विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य हवाई अड्डे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।' मोदी ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार उद्घाटन और शिलान्यास वाली चार बड़ी परियोजनाओं को गिनाते हुए कहा कि कम समय में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, 'पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था लेकिन आज भाजपा सरकार में वहीं नोएडा प्रदेश के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है।

मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन का यूडीएफ पर हमला, एसडीपीआई को लेकर झूठ फैलाने का आरोप

तिरूवनन्तपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) पर मलप्पुरम में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के समर्थन के संबंध में अपनी कॉरपोरेट समर्थक और वैश्वीकरणवादी नीतियों से ध्यान हटाने के लिए खुलेआम झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजयन ने कहा कि

एलडीएफ एक कर्मठ सरकार है जो अपने वादों को पूरा करती है और जनता द्वारा मान्यता प्राप्त ठोस विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। हालांकि, रमेश चेन्निथला और वी.डी. सतीशान जैसे नेताओं के नेतृत्व वाला यूडीएफ अब मलप्पुरम में एसडीपीआई के समर्थन को लेकर खुलेआम झूठ और निराधार आरोपों का सहारा ले रहा है ताकि अपनी कॉरपोरेट समर्थक, वैश्वीकरणवादी नीतियों से ध्यान भटका सके।

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष भले ही गलत सूचना फैलाने और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की एलडीएफ की रणनीति की आलोचना करने का प्रयास कर रहा है कि लेकिन सच्चाई यह है कि भले ही वे एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हों, आरएसएस नेतृत्व ने ही स्पष्ट रूप से यूडीएफ को वोट देने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता विपक्ष के राजनीतिक दुष्प्रचार को समझ सकती है और यह पहचान सकती है कि कौन सी पार्टी जनहितैषी रुख को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि अंततः, एलडीएफ हर मनगढ़ंत विवाद में नहीं उलझना चाहती क्योंकि जनता इन एजेंडों को भलीभांति समझती है और राजनीतिक दुष्प्रचार के बजाय सरकार के वास्तविक, जनहितैषी रुख को प्राथमिकता देती है।

अलग से, केरल सीपीआई (एम) के सचिव एमवी गोविंदन ने कांग्रेस नेता वीडी सतीशान की आलोचना की और भाजपा के प्रति पार्टी के विरोध का बचाव किया। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए गोविंदन ने कहा कि केरल के लोग जानते हैं कि सीपीआई (एम) वह ताकत है जो आरएसएस का कड़ा विरोध करती है, जबकि यूडीएफ वह पार्टी है जो उनसे संबंध रखती है। यदि आप मतदान के आंकड़ों का अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में भाजपा की जीत में किसने मदद की; यह सीपीआई (एम) ही थी जिसने नीमोम में भाजपा का खाता बंद कर दिया। यह एकमात्र विपक्षी दल है जिसने इस चुनाव में विकास के खिलाफ रुख अपनाया है।

गोविंदन ने वीडी सतीशान पर झूठ फैलाने और यूडीएफ के लिए जमात-ए-इस्लामी के सार्वजनिक समर्थन की निंदा न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वीडी सतीशान का मुख्य काम जागकर झूठ फैलाना है; हालांकि वे सांप्रदायिकता के खिलाफ होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने यूडीएफ के लिए जमात-ए-इस्लामी के सार्वजनिक समर्थन की घोषणा पर एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके अलावा, केएम शाजी सांप्रदायिकता की साक्षात मिसाल हैं; वे जहां भी चुनाव लड़ते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के अलावा कुछ नहीं बोलते।

कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, अमित शाह का ममता बनर्जी पर तीखा हमला

कोलकाता। अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में बोलते हुए कहा कि एसआईआर (न्यायिक सुरक्षा निरीक्षण) का अभ्यास पूरे देश में किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं भी न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए शाह ने पूछा, क्या यहां रखे गए घुसपैठियों को बंगाल का भविष्य तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की ओर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम देश से हर एक घुसपैठिए की पहचान करके उसे निष्कासित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, न केवल मतदाता सूचियों से बल्कि पूरे देश से, और यही मेरी पार्टी का एजेंडा है। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि टीएमसी की वोट बैंक की राजनीति के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा खतरे में है।

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा बंगाल के चुनावों से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है और यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से घुसपैठिए देश में प्रवेश कर रहे हैं और अशांति फैला रहे हैं। शाह ने बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा पीड़ित होने का नाटक करती हैं। उन्होंने कहा कि कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी उनके सिर पर पट्टी बंधी होती है, कभी वह बीमार पड़ जाती हैं, और फिर चुनाव आयोग के सामने असहायता का नाटक करते हुए संस्था को गालियां देती हैं। लेकिन मैं उन्हें यह बताने आया हूं कि बंगाल की जनता अब पीड़ित होने का नाटक करने की उनकी इस राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है।

अमरावती पर वाईएस शर्मिला का नायडू पर बड़ा हमला

बिना केंद्रीय सहायता के राजधानी निर्माण पर उठाए सवाल

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने अमरावती को राजधानी बनाने के विधानसभा प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन केंद्र सरकार से वित्तीय प्रतिबद्धता के अभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि क्या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत धन की मांग किए बिना केवल कानूनी बदलाव के आधार पर अमरावती का निर्माण संभव है।

वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कहा कि अमरावती को वैधानिक दर्जा देने वाला प्रस्ताव स्वागत योग्य है और केंद्र से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का अनुरोध भी उचित कदम है, लेकिन राजधानी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने अधिनियम के उस प्रावधान का उल्लेख किया जिसके अनुसार केंद्र सरकार को राजधानी निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि क्या केवल

अधिनियम में संशोधन कर देना पर्याप्त है या फिर वास्तविक निर्माण के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या अमरावती केवल एक राजपत्र अधिसूचना से ही वास्तविक रूप ले सकती है और क्या राज्य सरकार ने केंद्र को उसकी जिम्मेदारी के लिए पर्याप्त रूप से जवाबदेह ठहराया है।

शर्मिला ने कहा कि नई राजधानी के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना भी उसी का दायित्व है। उन्होंने प्रतीकात्मक कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि केवल औपचारिक घोषणाओं से काम नहीं चलेगा।

उन्होंने अमरावती के निर्माण की अनुमानित एक लाख करोड़ रुपये की लागत का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि इसका बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने गठबंधन सरकार से विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे जनता का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं।

तमिलनाडु चुनाव में द्रमुक गठबंधन का सीट साझेदारी सूत्र तय, कांग्रेस-वाम दलों समेत जानें किसे क्या मिला

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ द्रमुक ने अपने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को 28, डीएमडीके को 10, और वामपंथी दलों को पांच-पांच सीटें आवंटित की गई हैं, जिससे चुनावी मैदान की तस्वीर स्पष्ट हो गई है।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने शनिवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर ली, जिसमें कांग्रेस, वामपंथी दलों, वीसीके और डीएमडीके सहित अन्य दलों द्वारा चुनाव लड़े जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में द्रमुक धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। समझौते के अनुसार, द्रमुक की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस को 28 सीटों में पोन्नेरी, इरोड ईस्ट, विलावंकोड, शिवकाशी और करईकुडी शामिल हैं।

प्रेमलता विजयकांत के नेतृत्व वाली डीएमडीके को पहले ही 10 सीटें आवंटित की गई हैं, और उनमें विरुधाचलम और पल्लावरम शामिल हैं। थोल

थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली वीसीके को आठ सीटें मिली हैं, जिनमें कड्डुमन्नारकोइल, पनरुत्ती और तिंडीवनम शामिल हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पद्मनाभपुरम और पलानी सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थल्ली और भवानीसागर (अनुसूचित जाति) सहित अन्य सीटों से चुनाव लड़ेगी। दोनों वामपंथी दलों को पांच-पांच सीटें दी गई हैं। द्रमुक ने अन्य सहयोगी दलों के लिए भी सीटें निर्धारित की हैं, जिनमें वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके भी शामिल है, जो चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

असम में भाजपा का 'ऑपरेशन क्लीन', चुनाव से पहले 9 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया

गुवाहटी। असम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नौ बागी नेताओं को छह वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पार्टी में अनुशासन बनाए रखना और चुनाव के दौरान आंतरिक विवादों के प्रभाव को रोकना बताया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि जिन नेताओं ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उनके खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई है। निष्कासित नेताओं में उद्धव दास, जयंत कुमार दास, जितेंद्र सिंह गौर, अमलेंदु दास, धनजीत राभा, चक्रधर दास, गगन चंद्र हलोई, अंकुर दास और यशोदा दुलाल रक्षित शामिल हैं।

27 मार्च को जारी पत्र में राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि यह कार्रवाई पार्टी संविधान के प्रावधानों के तहत की गई है और सभी को तत्काल प्रभाव से छह वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिन पर आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का समर्थन करने का आरोप है। ऐसे छह कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है।

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब असम में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को मतगणना होगी। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है।

बीजेपी सत्ता में आती है, तो बुलडोजर चलाकर सब कुछ तबाह कर देगी, पुरुलिया में बोलीं ममता

कोलकाता। ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके सभी अधिकार और शक्तियां छीन ली गई हैं। मैं चुनी हुई मुख्यमंत्री हूं, लेकिन उन्होंने मेरी सारी शक्तियां छीन ली हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगढ़ में राम नवमी के दिन हुई हिंसा के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कहा, 'मुझे दोष मत दीजिए। मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। भाजपा के लोगों को यहां भेजा गया है। लेकिन वे नहीं जानते कि जीत हमारी ही होगी। रघुनाथगंज में दंगे भड़काए गए। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इन (अधिकारियों) का तबादला यहां इसलिए किया गया है ताकि वे दंगे भड़का सकें। रघुनाथगंज में दुकानों में तोड़फोड़ की गई... किसी के घर में तोड़फोड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया? रघुनाथगंज में दंगे भड़काने का अधिकार आपको किसने दिया? इन सबका हिसाब देना होगा।

ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल हमेशा

से विविधता में एकता के सिद्धांत में विश्वास रखता आया है। बंगाल समावेशिता और एकजुटता का प्रतीक है। बंगाल 'सभी का धर्म, सभी के त्यौहार!' के पवित्र दर्शन पर चलता है। लेकिन बंगाल धर्म के नाम पर हिंसा और गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रतिबंधित गायब आयोग का इस्तेमाल करते हुए, बीजेपी ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मनमाने तबादले करके राज्य प्रशासन को पंगु बना दिया है। और अब, वे चुनावों से पहले पूरे बंगाल में तनाव और अशांति फैलाने के लिए खुलेआम हिंसा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं।वे लोगों का दिल नहीं जीत सके, इसलिए वे डर के जरिए, अराजकता फैलाकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को भी माहौल को दूषित नहीं करने देंगे। हम गुंडागर्दी को अपनी एकता भंग नहीं करने देंगे।

मुर्शिदाबाद में राम नवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई स्थानों से पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। यह घटना रघुनाथगंज के मैकेन्ज़ी पार्क की ओर बढ़ रहे एक विशाल जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद झड़प में तब्दील हो गई। बनर्जी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो वे बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे और सबको बाहर निकाल देंगे। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि एसआईआ? तुम्हारे लिए मौत की घंटी साबित होगा। पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे और मतगणना 4 मई को होगी।

आरोग्य व स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा – महाराष्ट्र में एकीकृत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर जोर

दिव्यांश

मुंबई। स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र में एकीकृत तथा आधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से 'स्वास्थ्य और कल्याण में नवाचार – अगली पीढ़ी के उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना' विषय पर महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया।

पल्स वैद्यकीय सम्मेलन का आयोजन जियो विश्व व्यापार केंद्र में किया गया था। इस दौरान विभिन्न विचार गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया।

इस सत्र में विशेषज्ञों की चर्चा में यह बात सामने आई कि खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि चिकित्सक, शरीर चिकित्सा विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक के साथ दंत चिकित्सा का समन्वय भी अत्यंत आवश्यक है। यह भी बताया गया कि दंत स्वास्थ्य का खिलाड़ियों की ऊर्जा, पुनःस्थापन, एकाग्रता और शरीर के संतुलन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

इसके साथ ही यह आवश्यकता व्यक्त की गई कि अगली पीढ़ी के उत्कृष्टता केंद्र केवल उपचार केंद्र न होकर खेल चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पुनर्वास और कल्याण को शामिल करने वाली एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में विकसित किए जाएं।

इंग्लैंड क्रिकेट मंडल की सलाहकार डॉ. अनीता बिस्वास ने वैश्विक अनुभवों के आधार पर बताया कि खेल और व्यायाम चिकित्सा का विकास दीर्घकालीन योजना, शासन के सहयोग और सुव्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली पर आधारित होता है। विशेष रूप से 2012 के लंदन ओलंपिक के दौरान स्थापित एकीकृत व्यवस्था के कारण खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

इस अवसर पर लीड्स विश्वविद्यालय के सलाहकार डॉ. क्रेग झालेकी ने बताया कि खेल चिकित्सा के विशेषज्ञ बनने के लिए 8 से 9 वर्षों का गहन प्रशिक्षण आवश्यक होता है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा, विभिन्न विभागों का अनुभव तथा विशेष परीक्षाएं शामिल होती हैं।

दंत चिकित्सा के संदर्भ में डॉ. संदेश मयेकर ने बताया कि कम आयु से ही मुख सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, नियमित जांच तथा दांतों की सही संरचना खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाती है। साथ ही यह भी बताया गया कि मुख से संबंधित रोगों का प्रभाव हृदय रोग, मधुमेह और गुर्दा रोग जैसे गंभीर रोगों पर पड़ सकता है, इसलिए दंत स्वास्थ्य को भी स्वास्थ्य व्यवस्था में समान महत्व देना आवश्यक है।

नागपुर दंत महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता डॉ. विनय हजारे ने बताया कि भारत में मुख के कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसका प्रमुख कारण तंबाकू और निकोटीन का सेवन है। खेल क्षेत्र के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

महाराष्ट्र में खेल चिकित्सा और दंत चिकित्सा के समन्वय से एक प्रभावी और समग्र मॉडल विकसित करने पर भी चर्चा की गई, जो केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।

इस सत्र में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन भारतीय खेल दंत चिकित्सा अकादमी के संचालक डॉ. अतुल सुर्वे तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ सलाहकार अस्थि रोग शल्य चिकित्सक डॉ. रवी बेडगे ने किया।

खेड़ब्रह्मा - वडाली रेलखंड पर टेस्ट टिकट जारी, नई रेल सेवा शुभारंभ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा अवगत कराया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिनांक 31 मार्च, 2026 को गुजरात राज्य में ?891 करोड़ लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत खेड़ब्रह्मा - हिम्मतनगर - अहमदाबाद (असारवा) के मध्य नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ तथा खेड़ब्रह्मा - हिम्मतनगर रेलखंड का राष्ट्र को समर्पण शामिल है।

इसी क्रम में, आज दिनांक 28 मार्च, 2026 को खेड़ब्रह्मा से वडाली तक का सफलतापूर्वक ?10 मूल्य का टेस्ट टिकट जारी कर परिचालन की परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई, जो इस नई रेल सेवा के शुभारंभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परीक्षण यात्रियों के लिए टिकटिंग व्यवस्था, परिचालन प्रणाली एवं सुविधाओं की तैयारियों का सफल आकलन दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2026 को नई ट्रेन सेवा के शुभारंभ से पूर्व, स्थानीय सांसद एवं विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण 11वीं शताब्दी के प्राचीन ब्रह्मा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे तथा तत्पश्चात रेलवे स्टेशन पर भी विधिवत पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

खेड़ब्रह्मा, उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित एक प्राचीन एवं पवित्र धार्मिक नगरी है, जिसे ब्रह्माक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान ब्रह्मा, ऋषि भृगु एवं माँ अंबिका से जुड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां स्थित प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर, जिसे स्थानीय रूप से 'नाना अंबाजी' कहा जाता है, क्षेत्र की ग्रामदेवता के रूप में पूजित माँ अंबिका को समर्पित है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिक महत्व तथा समृद्ध आदिवासी संस्कृति के कारण विशेष पहचान रखता है।

मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक मारु-गुर्जर शैली में निर्मित है, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ, गर्भगृह एवं शांत परिसर दर्शनीय हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र वह स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था तथा देवी अंबिका ने असुरों का संहार कर साधुओं की रक्षा की थी। तभी से यह स्थल एक प्रमुख शक्ति उपासना केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने बताया कि यह नई रेल सेवा न केवल क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति देगी।

पल्स वैद्यकीय परिषद 2026 सफल; स्वास्थ्य क्षेत्र को परिवर्तन की नई दिशा: वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

15 समझौता करारों पर हस्ताक्षर

मुंबई। स्वास्थ्य और वैद्यकीय शिक्षा क्षेत्र में नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए पल्स वैद्यकीय परिषद 2026 महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है तथा इस परिषद से नवाचार, निवेश और सहयोग के नए मार्ग खुले हैं, ऐसा प्रतिपादन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ ने किया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री श्री मुश्रीफ ने कहा कि थोक औषधि उद्यान और औषधि निर्माण क्षेत्र पर हुई चर्चाओं से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा तथा नवउद्यमों की भागीदारी से नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इस उपक्रम से लगभग चार हजार विद्यार्थी, स्वास्थ्य व्यवसायी, शोधकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ होगा।

दो दिवसीय परिषद का अवलोकन करते हुए मंत्री मुश्रीफ ने कहा कि 'महाराष्ट्र घोषणा पत्र' से सहयोग, प्रारंभिक परियोजनाओं और व्यापक उपायों के लिए स्पष्ट दिशा प्राप्त हुई है। इससे परिषद केवल चर्चा तक सीमित न रहकर प्रत्यक्ष परिणाम देने वाली सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया।

पल्स वैद्यकीय परिषद 2026 में शासन, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय भागीदार एक साथ आने से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन संभव हैं, यह स्पष्ट हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय शिक्षा, नैदानिक नवाचार और निवारक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। परिषद में उच्च स्तरीय गोलमेज बैठकों, विभिन्न सत्रों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित तथा रोगी केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में महाराष्ट्र की प्रगति को रेखांकित किया गया।

इसके साथ ही शिक्षा, अनुसंधान और डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में 15 समझौता करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी।

वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मंत्री मुश्रीफ ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग सीमाओं से परे होना चाहिए। परिषद में प्रस्तुत विचारों को क्रियान्वित कर अधिक सुलभ, किफायती और भविष्य उन्मुख स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने का समय आ गया है, ऐसा उन्होंने आवाहन किया।

इस अवसर पर वैद्यकीय शिक्षण राज्य मंत्री माधुरी मिसाल सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे।

वडोदरा स्टेशन पर 'एयरपोर्ट जैसा अनुभव', गुजरात के पहले डिजिटल लाउंज का माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी द्वारा उद्घाटन

आधुनिक को-वर्किंग सुविधा के साथ यात्रियों के प्रतीक्षा अनुभव को मिला नया आयाम

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वडोदरा रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लाउंज / को-वर्किंग स्पेस विकसित किया गया है, जिसका आज माननीय सांसद डॉ. हेमांग जोशी एवं माननीय विधायक श्री केयूर रोकडिया द्वारा उद्घाटन किया गया।

ह सुविधा गुजरात में रेलवे स्टेशन पर? अपनी तरह की पहली तथा भारतीय रेल पर मुंबई सेंट्रल के बाद दूसरी है, जो वडोदरा स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं के नए स्तर पर ले जाती है।

इस अवसर पर सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने बताया कि वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आज 'विकसित वडोदरा से विकसित भारत' की झलक दिखाई देती है। जैसे एयरपोर्ट के अंदर ~~न्ध्छ~~ लाउंज होता है, वैसी ही सुविधा अब वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। यात्री अब एक ही स्थान पर मीटिंग, चाय-नाश्ता और विश्राम जैसी सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, बहुत ही किफायती दरों पर शॉवर और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह वडोदरा के लिए एक महत्वपूर्ण और गर्व का कदम है।

विधायक केयूर रोकडिया ने कहा कि वास्तव में, पहली बार वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी, नए फीचर्स का समावेश तथा कार्गो के लिए अलग डेक जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

इस अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने बताया कि माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में वडोदरा स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए इसे पश्चिम रेलवे के सबसे स्वच्छ स्टेशनों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में, 'उत्तम स्वच्छ स्टेशन' अभियान को आगे बढ़ाते हुए, एनएफआर पहल के अंतर्गत इस डिजिटल लाउंज की योजना बनाई गई है। वडोदरा के बरगद वृक्ष थीम पर आधारित यह लाउंज अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और यह यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा।

उन्होंने आगे बताया कि वडोदरा एक प्रमुख कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एवं बिज़नेस हब होने के साथ-साथ एकतानगर एवं धार्मिक स्थलों के कारण यात्रियों का प्रमुख केंद्र है। आने वाले समय में स्टेशन पर 18 महीनों में 4 नए पैदल ऊपरी पुल, दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार तथा हाई-स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार ने बताया कि यह डिजिटल लाउंज आधुनिक यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जिसमें हाई-स्पीड वाई-फाई, कार्य-स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक बैठने की व्यवस्था तथा कॉन्फ्रेंस सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी, चाय-नाश्ता एवं पेय पदार्थों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यात्रियों के लिए लचीली उपयोग योजनाएं, जैसे अल्पावधि बैठने की सुविधा, प्रति घंटे कार्य-स्थल उपयोग, विस्तारित लाउंज पैकेज, मीटिंग रूम बुकिंग तथा पे-पर-यूज़ सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, अधिक आराम के लिए लाउंजर/रिक्लाइनर सीटिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है।

यह डिजिटल लाउंज 24x7 संचालित होगा और इसमें रियल-टाइम ट्रेन सूचना प्रदर्शन, सीसीटीवी निगरानी, नियंत्रित प्रवेश, उन्नत शौचालय एवं कैशलेस भुगतान प्रणाली उपलब्ध होगी। स्वच्छता, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह पहल वडोदरा रेलवे स्टेशन को आरामदायक, आधुनिक और उत्पादक यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पश्चिम रेलवे की यात्री-केंद्रित सेवाओं को नई ऊंचाई देगा।

पश्चिम रेलवे चलाएगी पाँच स्पेशल ट्रेनें

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 02200/02199 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट स्पेशल (30 फेरे)

ट्रेन संख्या 02200 बांद्रा टर्मिनस - वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल प्रत्येक शनिवार 05:10 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर अगले दिन 05:00 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार 16:50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 16:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 02 अप्रैल, 2026 से 09 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, बियावरा राजगढ़, चाचौड़ा बीनागंज, रुठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, डबरा एवं दतिया स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 04126/04125 बांद्रा टर्मिनस - सूबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल (30 फेरे)

ट्रेन संख्या 04126 बांद्रा टर्मिनस - सूबेदारगंज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 17:00 बजे सूबेदारगंज पहुँचेगी। यह ट्रेन 07 अप्रैल, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04125 सूबेदारगंज - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार 05:20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 09:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, आगरा इडगाह, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 05184/05183 बांद्रा टर्मिनस - आजमगढ़ सुपरफास्ट स्पेशल (30 फेरे)

ट्रेन संख्या 05184 बांद्रा टर्मिनस - आजमगढ़ स्पेशल प्रत्येक सोमवार 10:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:10 बजे आजमगढ़ पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05183 आजमगढ़ - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक शनिवार 23:15 बजे प्रस्थान कर सोमवार को 08:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, बनारस, औंरीहर, मऊ एवं मोहम्मदाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 05034/05033 बांद्रा टर्मिनस - गोमती नगर स्पेशल (30 फेरे)

ट्रेन संख्या 05034 बांद्रा टर्मिनस - गोमती नगर स्पेशल प्रत्येक मंगलवार 23:00 बजे प्रस्थान कर गुरुवार को 07:45 बजे गोमती नगर पहुँचेगी। यह ट्रेन 07 अप्रैल, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05033 गोमती नगर - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार 14:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 अप्रैल, 2026 से 13 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 05018/05017 वलसाड - मऊ स्पेशल (30 फेरे)

ट्रेन संख्या 05018 वलसाड - मऊ स्पेशल प्रत्येक रविवार 15:10 बजे वलसाड से प्रस्थान कर मंगलवार को 00:45 बजे मऊ पहुँचेगी। यह ट्रेन 05 अप्रैल, 2026 से 12 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05017 मऊ - वलसाड स्पेशल प्रत्येक शनिवार 03:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12:35 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 अप्रैल, 2026 से 11 जुलाई, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा इडगाह, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर एवं बेल्थरा रोड स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 02200, 04126, 05184, 05034 एवं 05018 की बुकिंग 31.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

जलगांव में 'मौत का मिसफायर'! युवक दिखा रहा था देसी कट्टा, अचानक चली गोली ने ली दोस्त की जान

मुंबई। महाराष्ट्र के अमनेर (जलगांव) में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 'मिसफायर' की वजह से 35 साल के एक युवक की मौत हो गई. मृतक का नाम अरुण सुरेश प्लाज्मा बताया जा रहा है, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शुक्रवार रात यह हादसा उस वक्त हुआ, जब अरुण अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था. माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक एक लापरवाही ने सब कुछ बदल दिया और खुशी का माहौल मातम में बदल गया.

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के मुताबिक, रात करीब 9:15 बजे अरुण अपने दोस्तों के साथ माळीवाडा इलाके में बैठा था. इसी दौरान उसका एक दोस्त शत्रुघ्न महाराजा देसी कट्टे (पिस्तौल) के बारे में बता रहा था. बताया जा रहा है कि जब वह कट्टा दिखा रहा था, तभी अचानक उससे गोली चल गई. यह 'मिसफायर' सीधे अरुण के सीने में जा लगी. गोली लगते ही अरुण जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

अस्पताल ले जाते ही मौत

गोली लगने के बाद अरुण को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भी जांच शुरू कर दी. इस दौरान अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस मामले में अमनेर पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. शुरुआती तौर पर यह घटना हादसा लग रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु

ई-क्रय निविदा सूचना संख्या एस/15/2026, दिनांक 23.03.2026

अ.क्र.	निविदा संख्या	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी
95	09262086	विद्युत वाइपर मोटर	107 Nos	21-Apr-26
96	24265005	हल्का डीजल तेल (एलडीओ)	144 Kilo Ltr	17-Apr-26
97	11255048B	संलग्न परिशिष्ट-बी1 के अनुसार 06 स्थानों पर गड्ढा रहित इलेक्ट्रॉनिक गतिमान तौल पुल की आपूर्ति, स्थापना एवं प्रारंभ संचालन तथा समग्र वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध सहित	12 Nos	16-Apr-26
98	15265005	स्वचालित अग्नि पहचान प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना एवं प्रारंभ संचालन	30 Set	16-Apr-26

विस्तृत सूचना, बयाना राशि, क्रय प्रतिबंध तथा निविदा की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट www.ireps.gov.in तथा wr.indianrailways.gov.in देखें। 1256

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

त्वरित जल आपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था

मंडल रेल प्रबंधक (पश्चिमी), पश्चिमी रेलवे, छठा तल, अभियांत्रिकी विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008 द्वारा ई-निविदा सूचना संख्या बीसीटी/25-26/353 दिनांक 23.03.2026 आमंत्रित की जाती है। **कार्य एवं स्थानः** उधना में प्लेटफॉर्म संख्या 3, 4, 5 एवं टीवीआरएल 2 पर त्वरित जल आपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था (संयुक्त निविदा जिसमें विद्युत कार्य भी सम्मिलित है)। **कार्य की अनुमानित लागतः** 6,26,39,766.33 रुपये। **बयाना राशिः** 12,52,800 रुपये। **प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समयः** 17.04.2026 को 15:00 बजे तक। **खोलने की तिथि एवं समयः** 17.04.2026 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें। 1258

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

गाड़ी संख्या 12933/34 कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल में अस्थायी परिवर्तन मुंबई सेंट्रल से बांद्रा टर्मिनस तक

दिनांक 01.04.2026 से 27.04.2026 तक प्रारंभ होने वाली यात्रा के लिए लागू

गाड़ी संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस - वटवा कर्णावती एक्सप्रेस के समय में संशोधन		स्टेशन	गाड़ी संख्या 12934 अहमदाबाद - बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस के समय में संशोधन	
प्रस्थान	आगमन		प्रस्थान	आगमन
13:55 hrs.	-	बांद्रा टर्मिनस	-	12:30 hrs.

मध्यवर्ती स्टेशनों के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा

समय, ठहराव तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
Like us & Follow us on:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

सभी आरक्षित टिकटों के लिए कृपया मूल पहचान पत्र साथ रखें।

महाराष्ट्र में पाइप से प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक और तकनीकी सहायता की मांग – मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई। महाराष्ट्र में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने वाले नेटवर्क के विस्तार को तेज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तकनीकी सहायता और आधारभूत सुविधाओं हेतु विशेष आर्थिक निधि उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ ने की।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वे बोल रहे थे। यह बैठक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरदीप सिंह पुरी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रल्हाद जोशी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, केंद्रीय सचिव तथा महाराष्ट्र के अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर सहित विभिन्न महानगरपालिकाओं के आयुक्त और प्राकृतिक गैस कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मंत्री छगन भुजबळ ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई बार पड़ोसियों की सहमति न मिलने या महानगरपालिका से सड़क खुदाई की अनुमति में देरी के कारण गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रभावित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए अब 'गृहित अनुमति' व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत निर्धारित समय में अनुमति न मिलने पर इसे स्वीकृत माना जाएगा और कार्य आगे बढ़ाया जा सकेगा।

इसके साथ ही नए आवासीय परियोजनाओं को उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पाइप से गैस कनेक्शन अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन सोसायटियों में गैस पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां बिना कनेक्शन लिए उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर के उपयोग को कम कर पाइप गैस नेटवर्क के विस्तार के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। होटल, भोजनालय और लघु उद्योगों में पाइप गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से लागत कम होगी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए अनुमति और कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

गैस वितरण संस्थाओं को अब चौबीस घंटे कार्य करने की अनुमति दी गई है तथा उनके लिए कार्य अवधि में भी शिथिलता प्रदान की गई है।

राज्य में पाइप से प्राकृतिक गैस वितरण की प्रक्रिया तेज; उर्वरकों की उपलब्धता की लगातार समीक्षा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्र के प्रभावी नेतृत्व के कारण संकट में भी देश स्थिर; महाराष्ट्र सरकार केंद्र के निर्देशों का पूर्ण पालन करेगी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

वैश्विक संकट की पृष्ठभूमि में भारत ने संतुलित और प्रभावी नीति अपनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस संकट काल में महाराष्ट्र में पाइप से प्राकृतिक गैस का वितरण तेज किया जा रहा है तथा उर्वरकों की उपलब्धता की लगातार समीक्षा की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक दूरसंवाद माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की ओर से विभिन्न मुद्दे प्रस्तुत किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक इस बैठक में उपस्थित थे। मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी भी बैठक में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति से उत्पन्न वैश्विक संकट के दौरान देश के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए लिए गए निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा लागू उपायों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। आगामी खरीफ मौसम में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। इसके साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कृषि से संबंधित मामलों को कृषि संयोजन तंत्र से जोड़ने का कार्य जारी है, जिससे अनियमितताओं पर नियंत्रण होगा। स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सभी निर्देशों का पूर्ण पालन करेगी। पाइप से प्राकृतिक गैस का वितरण तेज किया गया है और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संकट के इस समय में राज्य सरकार केंद्र के नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट के कारण विश्वभर में व्यापक असर पड़ा है। कई देशों में राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू की गई है और व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ देशों में सप्ताह में अतिरिक्त अवकाश घोषित किए गए हैं, तो कहीं विद्यालय और कार्यालय बंद कर घर से कार्य व्यवस्था लागू की गई है। दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और मिस्र जैसे देशों में भी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि, भारत में स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई कमी से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में इसका बोझ नागरिकों पर नहीं डाला गया। राष्ट्र प्रथम, भारतीय प्रथम के सिद्धांत के अनुसार केंद्र सरकार ने स्वयं यह आर्थिक भार वहन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ग्यारह वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में किए गए परिवर्तन आज लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। पहले जहां 27 देशों से ईंधन आयात होता था, अब यह संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जिससे आपूर्ति बाधित होने का खतरा कम हुआ है।

विद्युत चालित बस और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर दिया गया जोर भी इस परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति से उत्पन्न परिस्थितियों पर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर टीवी अभिनेता ने की घरेलू सहायिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार!

मुंबई। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में एक टीवी अभिनेता को अपनी घरेलू सहायिका की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला पर तब हमला किया जब उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष मेश्राम के रूप में हुई है। इस अभिनेता ने कई टीवी धारावाहिकों में काम किया है। घटना मीरा रोड स्थित 'चांदेश अकॉर्ड' आवासीय परिसर की है, जहाँ पीड़िता सुमन नवाच हाउसकीपर के रूप में काम करती थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मेश्राम पिछले कुछ समय से सुमन पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था।

शनिवार को हुए इस हिंसक हमले के दौरान, मेश्राम ने चाकू से सुमन पर ताबड़तोड़ वार किए। आरोपी ने उसके पेट, छाती और गर्दन पर गहरे घाव किए। घायल अवस्था में सुमन को तुरंत गुरुकृपा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी आशीष मेश्राम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

वैज्ञानिक आधार बनाए रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा में नवाचार आवश्यक

दक्षता आधारित चिकित्सा शिक्षा संगोष्ठी में व्यक्त विचार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। चिकित्सा शिक्षा में वैश्विक दक्षता, अध्यापन और मूल्यांकन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नवाचार सामने आ रहे हैं तथा समुदाय आधारित उपचार प्रणाली स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा के बीच एक मजबूत कड़ी है, इसे महत्वपूर्ण बताया गया।

'पल्स' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित 'दक्षता आधारित चिकित्सा शिक्षा : सिद्धांत से व्यवहार तक' विषयक संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस संगोष्ठी में डॉ. ए. रेखा, डॉ. संजय जोडपे, डॉ. राकेश अग्रवाल, डॉ. नयनजीत मेघालय, डॉ. विवेक तथा शैला गुप्ता ने सहभागिता की।

चर्चा के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के विषय पर अपने विचार रखे।

डॉ. राकेश अग्रवाल ने जटिल चिकित्सीय जानकारी को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। मेघालय जैसे राज्यों में नर्सों के प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी कौशल के साथ-साथ संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता तथा संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, यह डॉ. नयनजीत ने बताया।

डॉ. विवेक सवजी ने कौशल विकास के लिए चरणबद्ध पद्धति की आवश्यकता पर बल दिया, वहीं डॉ. रेखा ने मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आंतरिक समन्वय की आवश्यकता बताई।

समुदाय आधारित शिक्षा को स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। कनाडा के अनुभव के आधार पर शैला गुप्ता ने इसकी उपयोगिता स्पष्ट की।

परीक्षा केंद्रित शिक्षा पद्धति में निरंतर और प्रतिक्रिया आधारित मूल्यांकन की आवश्यकता व्यक्त की गई। यह निष्कर्ष निकाला गया कि चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षकों को मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए सहानुभूति, संवेदनशीलता और डिजिटल साक्षरता को नैदानिक कौशल के साथ जोड़ना चाहिए।

चर्चा का संचालन डॉ. संतोष जोडपे ने किया। डॉ. सुधीर मेढेकर ने सहभागी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

पल्स सम्मेलन में विशेषज्ञों की भागीदारी और मत

एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई । निवारक स्वास्थ्य सेवा, पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक उपचार पद्धतियों के बीच समन्वय स्थापित कर एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक है, ऐसा मत स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने व्यक्त किया।

बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित जियो सम्मेलन केंद्र में आयोजित पल्स सम्मेलन में 'निवारक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना : सांस्कृतिक धरोहर से एकीकृत चिकित्सा व्यवस्था की ओर परिवर्तन' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।

संगोष्ठी में यह निष्कर्ष सामने आया कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रभावी हिस्सा बन सकती है। हालांकि, इसके लिए वैज्ञानिक आधार, प्रभावी नीतियां और सभी पद्धतियों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इस सत्र में निवारक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

डॉ. शुभाभ स्वैन (लेक व्यू स्वास्थ्य सेवा के निदेशक) ने कहा कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था में निवारक स्वास्थ्य सेवा को अधिक प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बीमारी होने के बाद उपचार करने के बजाय उसे पहले ही रोकने पर ध्यान देने से रोगियों की संख्या कम होगी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव भी घटेगा।

डॉ. संदीप बिपटे (कैंसर विशेषज्ञ, ब्रीच कैंडी अस्पताल) ने कैंसर जैसे गंभीर रोगों के संदर्भ में प्रारंभिक पहचान, जनजागरूकता और नियमित जांच के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां सहायक उपचार के रूप में उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक प्रमाण आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है।

डॉ. जयश्री लेले (भारतीय चिकित्सा संघ की महासचिव) ने आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की विश्वसनीयता को रेखांकित करते हुए पारंपरिक उपचार पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने के लिए स्पष्ट नीतियां, दिशा-निर्देश और विनियमन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सभी घटकों के बीच समन्वय जरूरी है।

डॉ. रूमी बेराम (महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर परिषद) ने एक्यूपंक्चर और अन्य पारंपरिक उपचार पद्धतियों के लाभों पर प्रकाश डालते हुए इन पद्धतियों को आधिकारिक मान्यता देने और स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक रूप से शामिल करने की आवश्यकता व्यक्त की।

डॉ. मनीषा उपेंद्र कोठेकर (राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग की अध्यक्षा) ने आयुष पद्धतियों (आयुर्वेद, योग, यूनानी आदि) और आधुनिक चिकित्सा को एकीकृत कर मजबूत और समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अनुसंधान, मानकीकरण और गुणवत्ता मानकों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

इस संगोष्ठी का संचालन जितेंद्र चोकसी ने किया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों को एकत्रित करते हुए एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया।

विद्यार्थियों को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं

'भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाला' योजना के अंतर्गत राज्य में 405 विद्यालयों के विकास को स्वीकृति- विद्यालय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और आधारभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाला' योजना के अगले चरण में 405 विद्यालयों के विकास को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय विकसित महाराष्ट्र-2047 की संकल्पना के अनुरूप है तथा विद्यालय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विश्वास व्यक्त किया है कि इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में शासन निर्णय प्रकाशित किया गया है।

इस निर्णय से राज्य के विद्यालयों की भौतिक और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को संतुलित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा विद्यालय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने बताया। पूर्व में प्रथम चरण में 478 विद्यालयों

का चयन किया गया था और उन विद्यालयों में कार्य अंतिम चरण में है। अब नवचयनित 405 विद्यालयों के माध्यम से राज्य के विद्यार्थियों को अधिक गुणवत्तापूर्ण और सुसज्जित शैक्षणिक तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस योजना के अंतर्गत समूह साधन केंद्र विद्यालय, प्रधानमंत्री श्री विद्यालय तथा विद्यानिकेतन विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस योजना के तहत बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, स्वच्छ पेयजल तथा आरओ या यूवी जल शुद्धिकरण सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही छात्राओं के लिए 'पिंक कक्ष' की सुविधा विकसित करने को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श विद्यालय को 'खेल अकादमी' के रूप में विकसित किया जाएगा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। शासन निर्णय में यह भी कहा गया है कि इस परियोजना के लिए आवश्यक निधि का वितरण शिक्षा संचालक (प्राथमिक) के माध्यम से जिलावार किया जाएगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़े और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय से निवारक स्वास्थ्य सेवा को नई दिशा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। 'स्वास्थ्य और निवारक चिकित्साशास्त्र में उभरती प्रौद्योगिकी – कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सटीक स्वास्थ्य के माध्यम से अधिक शीघ्र और बुद्धिमान रोकथाम' विषय पर वैद्यकीय सम्मेलन 2026 में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। पल्स वैद्यकीय सम्मेलन का आयोजन जियो विश्व व्यापार केंद्र में किया गया, जहां विभिन्न विषयों पर विचार गोष्ठियां आयोजित की गईं।

इस सत्र में विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आंकड़े और पारंपरिक ज्ञान का संयुक्त तथा जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने से अधिक प्रभावी, सटीक और निवारक स्वास्थ्य सेवा विकसित की जा सकती है। विशेषज्ञों ने इन तीनों के समन्वित उपयोग पर विशेष जोर दिया।

समग्र स्वास्थ्य के अध्यक्ष, संस्थापक एवं प्रशिक्षक डॉ. मिकी मेहता ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, योग, ध्यान और पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवीय अंतर्ज्ञान और जैविक तंत्रों का महत्व बना रहेगा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल सहायक साधन है।

स्वास्थ्य नवाचार विनिमय के सह-संस्थापक प्रदीप कक्कतील ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती बाजार व्यवस्था तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पहनने योग्य उपकरणों और आंकड़ा आधारित उपायों के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शासन, निजी क्षेत्र, निवेशक और विशेषज्ञों को मिलकर दीर्घकालीन निवेश और स्थायी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए तथा केवल लाभ पर केंद्रित होने के बजाय आम नागरिकों के लिए उपयोगी उपाय विकसित करना आवश्यक है।

हार्वर्ड चिकित्सा विद्यालय में शस्त्रक्रिया विषय की व्याख्याता तथा कैनोमिक्स संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सह-संस्थापक डॉ. लीना प्रधान ने आयुर्वेदिक वनस्पतियों और घटकों के वैज्ञानिक परीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से वनस्पतियों का मानव शरीर पर प्रभाव को आनुवंशिक स्तर पर समझना और लोगों को वैज्ञानिक जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है।

एआर अंतरराष्ट्रीय की संस्थापक डॉ. अलका मेहता ने त्वचा रोग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को स्पष्ट करते हुए भारतीय संदर्भ में सशक्त आंकड़ा तैयार करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि गलत निदान के जोखिम को देखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए।

शुगरफिट के सह-संस्थापक शिवतोष कुमार ने जीवनशैली संबंधी रोगों पर नियंत्रण के लिए आंकड़ा आधारित कार्यात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़े एकत्र करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके आधार पर जीवनशैली में उचित परिवर्तन आवश्यक है।

निहिलेंट के संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष एल. सी. सिंह ने मानवीय भावनाओं, विचार प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव भावनाओं को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम नहीं है।

पुणे में हैवानियत! लिफ्ट देने के बहाने पिस्तौल की नोंक पर महिला से रेप, कुरकुंभ इलाके में सनसनी

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तालुका के कुरकुंभ इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 32 साल की महिला के साथ रेप किया गया. यह वारदात 25 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे मुकादमवाड़ी, कुरकुंभ सीमा के पास हुई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने महिला को लिफ्ट देने का बहाना बनाया. जैसे ही महिला उसके गाड़ी में बैठी, आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर उसे धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती की. घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए दौंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले में तेजी दिखाते हुए दौंड पुलिस ने खड़की निवासी संदिग्ध आरोपी अमोल साहेबराव काले को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह की कोई वारदात तो नहीं की है।

ई-शासन में पर्यावरण विभाग पांचवें स्थान पर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों विशेष सम्मान

मुंबई। राज्य शासन के '150 दिनों की कार्य योजना' के अंतर्गत संचालित ई-शासन कार्यक्रम में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 159.29 अंकों के साथ मंत्रालयीन विभागों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों विभाग की सचिव जयश्री भोज को सम्मानित किया गया।

सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य एवं जानकारी प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, जिलाधिकारी तथा जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।

इस उपक्रम की सफलता के बारे में विभाग की सचिव जयश्री भोज ने बताया कि राज्य शासन की 150 दिनों की योजना के अंतर्गत नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सरल सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया। ई-कार्यालय, डैशफलक, संकेतस्थल एकीकरण तथा नई तकनीकों के उपयोग से विभाग की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आगे भी डिजिटल सेवाओं को और सशक्त बनाने पर जोर रहेगा।

उन्होंने बताया कि विभाग के कार्यों में गति लाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अजित पवार और विभाग की मंत्री पंकजा मुंडे का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 150 दिनों के ई-शासन कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग ने डिजिटल सेवाओं, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित पहल पर विशेष ध्यान दिया। विभाग के संकेतस्थल पर प्रतिदिन लगभग 3,000 नागरिक आते हैं और इसे दिव्यांगजन के लिए सुलभ तथा साइबर सुरक्षा के मानकों के अनुसार विकसित किया गया है। 'आपले सरकार' संकेतस्थल पर विभाग की सभी सात सेवाएं पूर्ण रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकृत व्यवस्था तैयार की गई है, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं मिल रही हैं।

ई-कार्यालय प्रणाली के कारण कार्य में तेजी आई है और मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच लगभग 5,450 फाइलों का निपटारा किया गया है। औसतन सात दिनों में फाइलों का निपटारा होने से प्रशासन अधिक प्रभावी हुआ है।

शिकायत निवारण व्यवस्था में भी सुधार किया गया है और अधिकांश शिकायतों का समाधान 7 से 15 दिनों के भीतर किया जा रहा है। साथ ही डैशफलक प्रणाली के माध्यम से कार्यों की तात्कालिक निगरानी संभव हो गई है। इसके अतिरिक्त, संदेश सेवा आधारित संवाद प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण एवं विध्वंस कचरा अनुमति सेवा संदेश सेवा के माध्यम से प्रदान करने की पहल भी शुरू की गई है।

इस उपलब्धि से पर्यावरण विभाग के डिजिटल परिवर्तन के प्रयासों को नई दिशा मिली है और नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में सहायता होगी।

सम्पादकीय

हिमालय क्षेत्र की बर्बादी से नेताओं को नहीं कोई सरोकार

देश के राजनीतिक दल देश के लोगों के लिए कितने गैरजिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में शोध पर आधारित दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी के बारे में किसी ने चिंता तक जाहिर नहीं की। इन रिपोर्टों में सर्दी के मौसम में हिमालय क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग के कारण और भूस्खलन के नए केंद्रों की जानकारी दी गई है। दरअसल ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेने पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। यही वजह है अत्यंत संवेदनशील और आम जन-जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जेसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जगह नहीं पाते हैं।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत महीना माना जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तराखंड के लिए यह धारणा गलत साबित हुई है। दिसंबर में उत्तराखंड में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जंगल की जमीन में नमी का लेवल बहुत कम है। उत्तराखंड की तरह, हिमाचल में भी पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से कोई बारिश नहीं हुई थी।

इसी तरह, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। देहरादून में तो कई बार यह इंडेक्स 300 के पार जा चुका है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से कराए गए एक अध्ययन ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरण प्रदूषण में फॉरेस्ट फायर की भूमिका 15 से 20 प्रतिशत तक है, जो कि बेहद गंभीर आंकड़ा है।

उत्तराखंड का हिमालयी भूगोल, जलवायु परिवर्तन और तेज विकास की दौड़ मिलकर राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में राज्य में तेज गति से सड़क निर्माण और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इसका परिणाम यह निकला कि चारधाम यात्रा रूट के आसपास लगभग 100 नए भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए। पहले से मौजूद संवेदनशील जोन भी और अधिक खतरनाक हो गए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन तेजी से निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया है। सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की गई, भारी मशीनरी का उपयोग हुआ, जंगलों का व्यापक कटान किया गया। इन सभी वजहों से पुराने भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हुए और नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन गए। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर करीब 400 भूस्खलन स्थल चिन्हित किए गए हैं।

उत्तराखंड में मानसून सीजन में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। साल 2025 के मानसून सीजन में अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई है। उत्तराखंड में 2016 से 25 तक प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। पिछले 11 वर्षों में 27,197 प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें अतिवृष्टि और भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख हैं। साल 2025 में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं, जिसमें 720 लोगों की मौत और 1207 लोग घायल हुए थे। इन 11 सालों के आंकड़े में केदारनाथ की साल 2013 में 16 और 17 जून को आई प्राकृतिक आपदा के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। उस दौरान अकेले केदारनाथ में ही 4400 से ज्यादा लोग या तो लापता हो गए थे या फिर मारे गए थे।

हिंदुकुश हिमालय का इलाका भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 11 बड़ी नदियां बहती हैं। वसंत के महीने में बर्फ पिघलने से ही इन नदियों को पानी मिलता है। लगभग 17 प्रतिशत आबादी पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। इसी पानी का उपयोग सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए भी किया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के तापमान में वैश्विक औसत से $0.74^{\circ}C$ अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साल 2003 से 2020 तक हिमालय के अधिकांश हिस्सों में बर्फ से घिरे इलाकों में गिरावट देखी गई। पहले यहां औसतन 102 दिनों तक बर्फ रहती थी। अब हर दस साल में पांच दिन कम हो रहे हैं।

जिम्मेदारों का गैरजिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार

विरोध के नाम विरोध या सत्ता के लालच में राष्ट्र-हित के नकार का कोई उदाहरण मिल सकता है तो वह हमारे देश में ही मिल सकता है। आज जब समूची दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है और अमेरिका व ईरान युद्ध के दुष्परिणामों से दुनिया के लगभग सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित हो रहे हैं उस दौर में देश में अराजकता का माहौल बनाये जाने के प्रयासों को किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समझ में नहीं आता कि देश में भय और अराजकता का माहौल बनाने से क्या हासिल हो सकेगा। आज दुनिया के देशों की एक दूसरे पर निर्भरता अधिक बढ़ी है। ऐसे में दुनिया के किसी भी कौने में कोई अप्रिय घटनाएं घटित होती है तो उसका प्रभाव कमोबेस दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है। सबको मालूम है कि कच्चे तेल और एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कोई आज की बात नहीं है। यह कोई हमारे देश की ही समस्या हो ऐसा भी नहीं है। बल्कि हार्मुज जलडमरुमध्य से जल यातायात को बाधित होने से यह समस्या और अधिक बढ़ी है। यह भी मालूम है कि ताजिंदगी के लिए किसी भी वस्तु की किसी भी देश द्वारा संग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि एलपीजी के हालिया संकट की ही बात की जाये तो होना तो यह चाहिए था कि ऐसे संकट के दौर में पक्ष-विपक्ष एक साथ खड़ा होता और ऐसे हालातों में आमजनता को पेनिक करने के

स्थान पर हालात से निपटने में सहभागी बनते तो एक जिम्मेदार पक्ष-विपक्ष या आम नागरिक की बात होती। पर हमने तो हालात ऐसे बना दिए जैसे एलपीजी का अकाल आ गया हो और चारों तरफ आंदोलन-प्रदर्शन के हालात बनाकर जमाखोरों को प्रोत्साहित करने और आमजन में भय का वातावरण बना दिया। जिसके घर में एलपीजी का सिलेण्डर था भी वह भी एक और सिलेंडर लाने की दौड़ में लग गया और इससे हालात बनने के स्थान पर बिगड़ने वाले होने लगे। होना तो यह चाहिए था कि विपक्षी भी सरकार के साथ खड़े होकर एक और आम जनता को हालात से निपटने के लिए प्रेरित करते वहीं दूसरी और ऐसे समन्वित प्रयास किये जाते जिससे विदेशों से एलपीजी लाने में आ रही दिक्कतों का हल खोजा जा सकता। गैरजिम्मेदारान हरकत तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार के प्रयासों से जब एलपीजी के दो जहाज होर्मुज जलडमरुमध्य से आने लगे तो यहां तक कहा जाने लगा कि इन जहाजों पर झण्डा अवश्य भारत का है पर इनमें उपलब्ध एलपीजी तो किसी अन्य देश के लिए है। धरने प्रदर्शन और हालात को बदतर बनाने के प्रयास किसी भी हालत में देशहित या देशवासियों के हित में नहीं कहे जा सकते। भले ही यह समझते हो कि हम देशवासियों के हित में सरकार को घेर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह सरकार को घेरना नहीं अपितु देश के प्रति अपने दायित्वों से हटने और पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना गतिविधि ही कही जानी चाहिए।

यह वहीं भारत देश है जब लाल बहादुर शास्त्री के समय अन्न संकट आया तो एक आह्वान पर छोटे बड़े सभी ने एक दिन सोमवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग आज भी उस आह्वान के चलते आज भी सोमवार का व्रत करते हुए मिल जाएंगे। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के समय समूचा देश इन्दिरा गांधी के साथ एक स्वर में स्वर मिला रहा था। आज पता नहीं ऐसे हालात कैसे होने लगे हैं कि ऑपरेशन सिन्दुर, सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य सैन्य गतिविधियों पर भी प्रश्न उठाये जाने लगे हैं। संभवतः दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की बात नहीं होती होगी।

जहां तक एलपीजी की बात है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब एलपीजी कनेक्शन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में भी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से भी दो चार होना पड़ता था। धरातल पर देखेंगे तो हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत है। देश में 31 करोड़ सक्रिय एलपीजी धरेलू कनेक्शन है। समूचे देश की बात की जाए तो प्रतिदिन ओसतन 50 से 60 लाख एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता होती है। ऐसे में मांग और आपूर्ति बनाये रखना अपने आप में दुष्कर है पर हालिया संकट को अलग कर दिया जाए तो पिछले कुछ सालों से एलपीजी या पेट्रोल आदि को लेकर देश में किसी तरह का संकट देखने को नहीं मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार्मुज जलडमरुमध्य से दो जहाज भारतीय तट पर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा भारतीय जहाजों को निर्बाध रुप से रास्ता दिलाने के प्रयास जारी है। ऐसे हालातों के बावजूद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना बड़ी बात है।

इस संकट के दौर में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व हो जाता है। हालात हमारे सामने हैं, सरकार के प्रयास भी हमारे सामने हैं, ऐसे में जमाखोरी और कालाबाजारी को निरुत्साहित करना हम सबका दायित्व होना चाहिए। आवश्यकता नहीं होने पर भी जबरदस्ती सिलेण्डर का स्टॉक करने से बचना चाहिए। वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने में सहभागी बनना चाहिए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक जबरदस्ती पेनिक होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे तत्व जो हालात को व्यवस्थित करने के स्थान पर बिगाडने व पेनिक करने व जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोत्साहित कर रहे हो उन्हें बेनकाब करने के लिए आगे आना होगा। यदि ऐसे दौर में हमें एक जुट होना होगा और राष्ट्रहित को ही सर्वोपरी मानना होगा।

नौकरी की दौड़ में खोती शिक्षा

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दबाव में शिक्षा की बुनियाद कमजोर होती जा रही है।

डॉ. प्रियंका सौरभ

आज का युवा ऐसे समय से गुजर रहा है, जब अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता पहले से कहीं अधिक जटिल और प्रतिस्पर्धी हो गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती संख्या, उनकी लंबी प्रक्रिया और अनिश्चित परिणाम, खासकर सरकारी नौकरियों के लिए, ने छात्रों और अभिभावकों दोनों को गहरी उलझन में डाल दिया है। इस संदर्भ में साझा पात्रता परीक्षा (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) को एक बड़ी उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव इस उम्मीद पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

हरियाणा में वर्ष 2019 से 2024 के बीच पांच वर्षों की अवधि में परीक्षा प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी। परिणामस्वरूप, इस अवधि में केवल एक ही परीक्षा पूरी तरह संपन्न हो पाई, और उससे जुड़ी कुछ भर्तियां अभी भी न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं। यहां तक कि वर्ष 2024-25 चक्र में भी अब तक केवल प्रारंभिक परीक्षा ही आयोजित की गई है। जिस धीमी गति से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह आशंका निराधार नहीं है कि अंतिम परिणाम आने में काफी समय लग सकता है।

लेकिन यह समस्या केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की स्थिति लगभग सभी राज्यों में कमोबेश एक जैसी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और यहां तक कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी भर्ती परीक्षाओं में देरी, प्रश्नपत्र लीक, न्यायिक विवाद और परिणामों में विलंब जैसी समस्याएं लगातार सामने आती रही हैं। कई राज्यों में वर्षों तक परीक्षाएं आयोजित नहीं होतीं, और जब होती हैं तो उनकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि वह अभ्यर्थियों की उम्र और धैर्य दोनों की परीक्षा लेती है।

इसका युवाओं के मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर साल लाखों छात्र स्नातक होकर रोजगार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उपलब्ध सरकारी पदों की संख्या बेहद सीमित होती है। उदाहरण के लिए, यदि देशभर से लाखों अभ्यर्थी किसी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, तो चयनित होने वालों की संख्या हजारों तक ही सीमित रहती है। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी को ही अंतिम लक्ष्य मान लेना और केवल उसी पर निर्भर रहना अत्यंत जोखिम भरा निर्णय बन जाता है।

इस पूरे परिदृश्य का सबसे चिंताजनक पहलू 'अनुपस्थिति संस्कृति' का तेजी से फैलना है। देश के लगभग हर राज्य में एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, जहां छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर नियमित रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालय की कक्षाओं से दूर रहने लगे हैं। उन्हें लगता है कि सफलता पाने के लिए पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह अलग हो जाना आवश्यक है। लेकिन यह सोच धीरे-धीरे उनके भविष्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। वास्तव में, कॉलेज जीवन केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता। यह वह समय होता है, जब छात्र का बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। कक्षा में भागीदारी, शिक्षकों के साथ संवाद, समूह चर्चा, प्रस्तुतियां और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां-ये सभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब छात्र इन अवसरों को खो देते हैं, तो वे केवल विषय ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के आवश्यक कौशलों से भी वंचित रह जाते हैं।

अनुपस्थिति संस्कृति का एक और गंभीर दुष्प्रभाव यह है कि छात्रों की शैक्षणिक नींव कमजोर हो जाती है। वे विषय को गहराई से समझने के बजाय केवल परीक्षा पास करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के बाद उनके पास न तो मजबूत शैक्षणिक रिकॉर्ड होता है और न ही कोई वैकल्पिक करियर विकल्प। परिणामस्वरूप, उनका आत्मविश्वास गिरता है और वे मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज का समय अत्यंत तकनीकी रूप से उन्नत है। डिजिटल माध्यमों ने शिक्षा में क्रांति ला दी है। ऑनलाइन कोचिंग, वीडियो व्याख्यान, डिजिटल नोट्स, परीक्षा श्रृंखलाएं और आभासी कक्षाएं देश के हर कोने में उपलब्ध हैं। इसलिए यह धारणा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कॉलेज छोड़ना जरूरी है, पूरी तरह गलत है। छात्र अपनी नियमित पढ़ाई के साथ-साथ भी प्रभावी ढंग से तैयारी कर सकते हैं।

संतुलित और व्यावहारिक रणनीति अपनाकर छात्र अपने स्नातक के तीन वर्षों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। पहले वर्ष में उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ-साथ सामान्य ज्ञान, समाचार पत्र और समसामयिक घटनाओं से जुड़ना चाहिए। इससे उनकी बौद्धिक नींव मजबूत होती है। दूसरे वर्ष में वे गणित, तर्कशक्ति और भाषा जैसे विषयों पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। साथ ही वे अपने मूलभूत सिद्धांतों को पुस्तकों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। अंतिम वर्ष तक उन्हें यह स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि वे उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं।

देश के विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा और निजी क्षेत्र के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, नवाचार, कौशल आधारित कार्य और स्वतंत्र कार्य जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए द्वार खुल रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि छात्र अपने विकल्पों को केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रखें, बल्कि अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का अन्वेषण करें।

इस पूरे परिदृश्य में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने मित्रों या समाज के दबाव में कक्षाओं से दूर रहने का निर्णय लेते हैं, और अभिभावक उन पर भरोसा करते हुए इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि अभिभावक इस निर्णय के दीर्घकालिक प्रभावों को समझें और अपने बच्चों को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें। केवल एक परीक्षा या एक करियर विकल्प पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है।

आज के प्रतिस्पर्धी युग में सफलता उन्हीं को मिलती है, जो लचीलेपन को अपनाते हैं और अपने लिए अनेक विकल्प खुले रखते हैं। छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी शैक्षणिक क्षमता को मजबूत करें और साथ ही कौशल विकास पर भी ध्यान दें। संचार कौशल, तकनीकी दक्षता, समस्या समाधान की क्षमता और आत्मविश्वास-ये सभी गुण उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि साझा पात्रता परीक्षा या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा केवल एक अवसर है, न कि अंतिम लक्ष्य। इसे जीवन का एक हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि संपूर्ण आधार। यदि छात्र अपनी पढ़ाई, कौशल और व्यक्तित्व विकास पर समान ध्यान दें, तो वे न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

समय की मांग है कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए-जहां तैयारी और शिक्षा, लक्ष्य और विकल्प, दोनों का समन्वय हो। तभी हमारा युवा न केवल नौकरी की दौड़ में सफल होगा, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

निजी स्कूलों की महंगी फीस, बड़े दावे और हकीकत

डॉ. सत्यवान सौरभ

आज के दौर में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय भी बन चुकी है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके साथ-साथ बढ़ रही है उनके प्रचार-प्रसार की रणनीतियाँ। अखबारों, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया और यहां तक कि स्थानीय कार्यक्रमों में भी स्कूलों के आकर्षक विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हर स्कूल अपने आप को 'सर्वश्रेष्ठ', 'भविष्य निर्माता' और 'सफलता की गारंटी' देने वाला संस्थान बताता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये दावे वास्तविकता से मेल खाते हैं, या फिर यह केवल अभिभावकों की उम्मीदों और भावनाओं का लाभ उठाने का एक तरीका है?

आज का अभिभावक पहले से कहीं अधिक जागरूक है, लेकिन साथ ही वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित भी है। वह चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। इसी सोच के चलते वह अक्सर अपनी आय से अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों में कटौती करके, कर्ज लेकर या अतिरिक्त काम करके बच्चों की फीस भरते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि महंगे स्कूल में पढ़ाई का मतलब है बेहतर शिक्षा और निश्चित सफलता।

निजी स्कूल इसी मनोविज्ञान को समझते हैं और अपने प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करते हैं। वे अपने कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, एयर-कंडीशंड सुविधाओं, खेल गतिविधियों और अन्य आधुनिक संसाधनों को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके साथ ही, वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और रक्षा सेवाओं में सफलता के बड़े-बड़े दावे भी करते हैं। कई बार विज्ञापनों में कुछ चुनिंदा छात्रों की उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह पूरे स्कूल के स्तर को दर्शाती हो।

लेकिन जब हम इन दावों को गहराई से परखते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वास्तविकता यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। चाहे वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षाएं हों, या फिर कानून और रक्षा सेवाओं से जुड़ी परीक्षाएं-इनमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या अक्सर सीमित होती है। कई बार तो पूरे साल में गिने-चुने छात्र ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्कूल द्वारा किए गए दावे वास्तविकता के अनुरूप हैं?

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल स्कूल की पढ़ाई के आधार पर संभव नहीं होती। अधिकतर छात्र अलग से कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, जहां उन्हें विशेष रूप से इन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। वे अतिरिक्त समय, मेहनत और संसाधन लगाते हैं। ऐसे में यदि कोई स्कूल इन छात्रों की सफलता का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेता है, तो यह अभिभावकों को गुमराह करने जैसा हो सकता है।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी किसी स्कूल की गुणवत्ता को मापने का एक प्रमुख आधार होते हैं। लेकिन यहां भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत कम छात्र ही 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं। 95 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों की संख्या तो और भी कम होती है। यदि कोई स्कूल खुद को क्षेत्र का अग्रणी संस्थान बताता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसके परिणाम भी उसी स्तर के हों। लेकिन कई बार यह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती।

फीस का मुद्दा इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पहलू है। निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, और कई मामलों में यह मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाती है। फीस के अलावा भी कई तरह के अतिरिक्त खर्च होते हैं-जैसे परिवहन शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबें, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क आदि। कुल मिलाकर, एक बच्चे की शिक्षा पर होने वाला खर्च काफी अधिक हो जाता है।

यहां यह समझना जरूरी है कि स्कूलों को अपने संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छे शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां-इन सभी का एक खर्च होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब फीस और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच संतुलन नहीं होता। यदि स्कूल अत्यधिक फीस ले रहा है, तो उससे यह अपेक्षा करना गलत नहीं है कि वह उसी स्तर की गुणवत्ता भी प्रदान करे।

सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कई राज्यों में फीस नियंत्रण के लिए नियम और कानून बनाए हैं। फीस रेगुलेशन कमेटियां गठित की गई हैं, जिनका उद्देश्य स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है। लेकिन व्यवहार में इन नियमों का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। कई बार अभिभावकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, और वे अकेले आवाज उठाने से हिचकिचाते हैं।

इस स्थिति में अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें केवल विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय स्कूल के वास्तविक प्रदर्शन, शिक्षकों की गुणवत्ता, और पिछले परिणामों का गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। यदि संभव हो, तो अन्य अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए और उनके अनुभव जानने चाहिए। स्कूल के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर को समझना आवश्यक है।

इसके अलावा, यदि अभिभावकों को लगता है कि स्कूल पारदर्शिता नहीं बरत रहा है या गलत दावे कर रहा है, तो उन्हें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए। एकजुट होकर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगना, और आवश्यक होने पर संबंधित शिक्षा अधिकारियों या बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराना, एक प्रभावी कदम हो सकता है। इससे न केवल समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोका भी जा सकता है।

यह भी जरूरी है कि हम सफलता की परिभाषा को केवल अंकों और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित न रखें। हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां और क्षमताएं भी अलग होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। एक अच्छा स्कूल वही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करे।

आज के समय में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी स्कूल सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। स्कूल केवल एक मंच प्रदान करता है, जहां से बच्चा अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना मेहनत करता है, उसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है, और उसका वातावरण कैसा है।

अंततः, शिक्षा को एक सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक व्यापार के रूप में। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता बनाए रखें, अपने दावों के प्रति जवाबदेह रहें, और अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखें। वहीं, अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जागरूक रहें, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवाज उठाएं।

यदि इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन और विश्वास बना रहता है, तभी हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सके, न कि केवल एक महंगा सौदा बनकर रह जाए।

जैविक खेती व गंगा संरक्षण पर अधिकारियों को मिले निर्देश

जिला वृक्षारोपण,पर्यावरण, गंगा समिति की बैठक सीडीओ की अध्यक्षता में सम्पन्न

समीक्षा बैठक में पर्यावरण संरक्षण एवं गंगा स्वच्छता पर जोर

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार के मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति,गंगा समिति, प्रदूषण ,पर्यावरण के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्टेट्रट सभागार में सम्पन्न हुई।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा, तभी हम लोग भी सुरक्षित होंगे, जो पेड़ लगाये गये है उन पेड़ों का बचाव का प्रयास हम करेंगे संकल्प लें। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण करने हेतु दिए गए प्रारूप में डाटा फीड कर उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। पौधों के रखरखाव एवं अन्य बिंदुओं पर बल दिया गया।

जिला पर्यावरण समिति के अंतर्गत जनपद में उत्पन्न हो रहे गीला कचरा के उपचार हेतु उपलब्ध वेट कंपोस्टिंग पिट की कार्यात्मक स्थिति की समीक्षा की गई। जनपद में उत्पन्न हो रहे प्लास्टिक अपशिष्टों को रिसायकल एवं प्रबन्धन (सड़क निर्माण, ऊर्जा निर्माण इत्यादि में) हेतु की जा रही कार्यवाही की गयी। समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट ट्रांसफर स्टेशन, डम्पिंग साईट क्षमता एवं कार्यात्मक स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट पर बल दिया गया। जनपद में उत्पन्न हो रहे कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट के उचित निस्तारण एवं प्रबन्धन हेतु की जा रही कार्यवाही की गयी। जनपद में उत्पन्न हो रहे ठोस अपशिष्ट के उपचार एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन (वेस्ट टू कम्पोस्ट एवं वेस्ट टू एनर्जी) हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी। जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के फण्टलाईन स्टाफ के कार्यात्मक क्षमता की अभिवृद्धि हेतु किये जा रहे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। जनपद में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी।

जिला गंगा समिति के अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित शव दाह गृह का संचालन विद्युत से किया जाय जिससे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकें। गंगा ग्रामों में किसानो को जैविक खेती हेतु प्रेरित किया जाय तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति आम जनमानस में जन जागरूकता हेतु अभियान चलाया जाय। जनपद में संचालित समस्त डाईंग प्लान्ट से निसृत हो रहें तरल अपशिष्ट की गुणवत्ता की जांच की जाय साथ ही गुणवत्ता मानक अनुरूप न होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायें। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोबिन्द शुक्ल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बढ़ते खतरे के जनपदवासियों को जागरूक करते हुए सीडीओ ने जनपदवासियों से कपड़े वाले थैले या बायोडिग्रेबल थैले में समान लेने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी विवेक यादव, एसीएमओ डॉ ओपी शुक्ला, डीआईओ डॉ पंकज कुमार एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिकगण उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में पारदर्शिता बढ़ाने की नई पहल, अब शिकायतकर्ताओं की फोटो व पर्ची ऑनलाइन अपलोड

भदोही।जनपद में जनसुनवाई प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने सराहनीय पहल की है। नई व्यवस्था के तहत अब पुलिस कार्यालय आने वाले प्रत्येक फरियादी की मौके पर फोटो ली जा रही है और उन्हें दी जाने वाली प्राप्ति रसीद (पर्ची) को तत्काल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

इस तकनीकी प्रणाली का उद्देश्य शिकायतों की ट्रैकिंग को मजबूत करना और उच्चाधिकारियों द्वारा रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करना है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुआ है और उसकी समस्या सही तरीके से दर्ज की गई है।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध होना चाहिए, ताकि पीड़ित को वास्तविक न्याय मिल सके। इस व्यवस्था से न केवल शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी।

इसके साथ ही जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनसुनवाई से जुड़े अभिलेखों को अद्यतन रखें और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए आम जनता का विश्वास और मजबूत करें।

जिला जज ,डीएम, एएसपी द्वारा जिला कारागार का किया गया संयुक्त निरीक्षण

विभिन्न बैरकों, रसोई घर, डिस्पेंसरी आदि का लिया गया जायजा

भदोही । जनपद न्यायाधीश अखिलेश दूबे, जिलाधिकारी शैलेष कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक शिवम अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार ज्ञानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होने जेल में बन्द कैदियों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली, तथा जेल अधीक्षक को सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं को समय से बन्दियों को मुहैया कराने का निर्देश दिया। इस दौरान ज्ञानपुर जिला जेल में निरुद्ध जनपद भदोही के पुरुष/महिला बैरकों में जाकर सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक ने रसोई घर, स्टोर खाद्यान, महिला बैरक/पुरुष बैरक/ किशोर बैरक, के निरीक्षण के साथ ही जेल कैम्पस में ही संचालित डिस्पेन्सरी का भी निरीक्षण किया तथा डिस्पेन्सरी में मौजूद दवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। तत्पश्चात सभी अधिकारियों ने महिला बैरक में पहुच कर उन्हें जेल प्रशासन द्वारा मुहैया करायी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की तथा उन्हें सरकार द्वारा प्रदत सभी सुविधाएं समय पर मुहैया कराये जाते रहने का निर्देश दिया। उपर्युक्त लोगों ने पेयजल व्यवस्था, शौचालय, साफ-सफाई आदि का निरीक्षण के साथ ही मुलाकाती पंजिका का भी अवलोकन किया। कारागार अधीक्षक ने कारागार का अवलोकन कराया।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

1 अप्रैल से शुरू होने वाले अभियान की तैयारियों की समीक्षा, समयबद्ध सुचारू रूप से कार्य के निर्देश

भदोही। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में द्वितीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में आहूत की गई। बैठक में 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग अपने-अपने प्रस्तुत माइक्रो प्लान के अनुसार कार्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता के लिए विभागीय समन्वय एवं जमीनी स्तर पर सक्रियता अत्यंत आवश्यक है।

जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सभी विभागों द्वारा अपने-अपने माइक्रो प्लान जमा कर दिए गए हैं। साथ ही ब्लॉक स्तर पर अध्यापकों एवं ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 4 अप्रैल से 8 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि दस्तक अभियान 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचालित होगा, जिसके अंतर्गत आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करेंगी तथा रोगियों की पहचान कर उन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार हेतु प्रेरित करेंगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान साफ-सफाई, जलभराव निस्तारण, फॉगिंग एवं जनजागरूकता गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष चक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, समयबद्ध कार्य एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश

भदोही। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी कार्य एवं वित्तीय प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जिससे पारदर्शिता एवं समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सुरियावां पर हुए अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग के समन्वय से तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश चिकित्सा अधीक्षक को दिया। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जंगीगंज स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स प्रतिभा गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अभोली में तैनात करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही, कार्यक्रमों के संचालन एवं अनुश्रवण में शिथिलता पाए जाने पर डीपीएम रोली श्रीवास्तव का मानदेय रोकने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग आमजन से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी डॉक्टर समय से उपस्थित रहकर मरीजों का समुचित उपचार सुनिश्चित करें , किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने यू0पी0 एमओआईसी, आशा व एएनएम की हफ्ते में बैठक कर सघन समीक्षा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बैठक की कार्यवृत्ति में सभी बिन्दुओं की समीक्षा अगले दिन तक अवश्य उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुष्मान आरोग्य मन्दिर में लैब स्लैब हेल्थ डैशबोर्ड के विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। स्वास्थ्य विभाग के हर कार्यक्रम की कंपोजिट रिपोर्ट अगले बैठक में प्रस्तुत किया जाए। सभी एवं बेसिंग उपलब्धता पर बल दिया। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉक्टरों के उपस्थिति की चेकिंग एवं कार्य के प्रति उनकी दक्षता का सतत् मूल्यांकन हो। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में व्यक्तिगत व टीम बेस्ड इंटेंसिव बढ़ाने व सुधार करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। सभी पीएचसी, सीएचसी पर ड्यूटीरूम सहित सभी जगह साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सभी एमओआईसी को निर्देशित किया कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाये, इस सन्दर्भ में आशा व एएनएम को प्रेरित करें। प्रसूता को कम से कम 48 घण्टे अस्पताल में रूकने हेतु प्रेरित किया जाय। जिलाधिकारी ने जनपद में कार्यरत सभी कम्युनिटी आफिसर को निर्देशित किया कि आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की प्रभावी क्रियाशीलता हेतु अटेन्डेंस के माध्यम से नियमित करें, लापरवाही न बरते। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संतोष कुमार ने सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला उद्योग बंधु व निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक, व्यापारियों की समस्याओं पर मंथन

भदोहीः कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला उद्योग बंधु एवं जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों, व्यापारियों और उद्यमियों के साथ व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों, सुविधाओं और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापारियों और उद्यमियों से संबंधित मामलों का निस्तारण समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए विभागीय अधिकारियों को सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा।

सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने लीड बैंक सहित सभी बैंकों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत कर वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बैंकों की प्रगति धीमी है, उनकी दैनिक मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए लैंड बैंक डाटा, प्लेज पार्क के विकास, 'सिटी ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' और 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब' जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया।

इसके अलावा बुनकरों से संबंधित लाइसेंस मुद्दे, चिल्ह-गोपीगंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण और नए उद्योगों की स्थापना जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों व उद्यमियों ने जमीन व राजस्व से जुड़ी समस्याएं उठाईं, जिस पर अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर समाधान का भरोसा दिलाया।

बैठक में उपायुक्त उद्योग दया शंकर, विद्युत विभाग के अधिकारी, निर्यातक, व्यापारी व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उद्योगों को बढ़ावा देने और व्यापारिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

थाना समाधान दिवस में 78 शिकायतें आईं, 15 का मौके पर निस्तारण

भदोहीः जनपद के समस्त थानों पर शनिवार को 'थाना समाधान दिवस' का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण का प्रयास किया गया। कोतवाली ज्ञानपुर में जिलाधिकारी शैलेष कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई, जहां अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनीं।

जनसुनवाई के दौरान जनपद भर में कुल 78 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 72 राजस्व विभाग व 6 पुलिस विभाग से संबंधित थे। इनमें से पुलिस विभाग के सभी 6 और राजस्व विभाग के 9 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों के समाधान के लिए पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम गठित कर शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने विशेष रूप से भूमि संबंधी मामलों में संयुक्त कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि फरियादियों को अलग-अलग भटकना न पड़े और उन्हें समयबद्ध न्याय मिल सके। इस दौरान एएसडीएम ज्ञानपुर शिव प्रकाश, थाना प्रभारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

दर्जनों गांवों में अनिल चौधरी का जनसंपर्क, लोगों से किया सीधा संवाद

सिद्धार्थनगर जिले में अपना दल (एस) के प्रदेश सचिव (शिक्षा मंच) अनिल चौधरी ने शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सिसवा बुजुर्ग, बहुति, पकरैला, मेहदानी, औरहवा, परसा देवाईचपार व देवियापुर सहित कई गांवों में पहुंचकर आमजन से संवाद स्थापित किया। जनसंपर्क के दौरान अनिल चौधरी ने लोगों से सीधे बातचीत करते हुए पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठन की दिशा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि अपना दल (एस) लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान के लिए प्रयासरत है। पार्टी का उद्देश्य कमजोर, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकार, सम्मान और विकास को सुनिश्चित करना है। अनिल चौधरी ने यह भी कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के उत्थान और सभी वर्गों को बिना भेदभाव समान अवसर उपलब्ध कराना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के साथ, जनता के लिए पार्टी का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रकाश चन्द, लालजी चौधरी, ओमप्रकाश, राजेश अग्रहरि, राम तीरथ शुक्ला, बुध सागर शुक्ला(ग्राम प्रधान) सुरेंद्र गुप्ता, मनोज यादव, उदय भान साहनी सहित स्थानीय कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

भिवंडी में बेटियां निशाने पर, एक ही दिन में तीन नाबालिग लड़कियां लापता

घर से निकलीं और फिर नहीं लौटीं, अपहरण की आशंका से मचा हड़कंप.

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शहर में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ही दिन में अलग-अलग थाना क्षेत्रों से तीन नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता होने की घटनाओं ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण के मामले दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

पहली घटना शांतिनगर थाना क्षेत्र की है, जहां 14 वर्षीय लड़की दोपहर करीब साढ़े बारह बजे घर से बाहर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने हर संभव जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। दूसरी घटना नारपोली क्षेत्र की है। यहां 16 वर्षीय किशोरी दोपहर के समय घर से अचानक गायब हो गई। परिजनों के मुताबिक वह बिना किसी को बताए घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। तीसरा मामला निजामपुरा इलाके का है, जहां 13 वर्षीय लड़की सुबह घर से निकली थी और तब से लापता है। परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाने की आशंका है। तीनों मामलों में समानता यह है कि लड़कियां बिना किसी सूचना के घर से निकलीं और फिर उनका कोई सुराग नहीं मिला।

पुलिस को शक है कि इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित गिरोह भी हो सकता है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सुत्रों के अनुसार सभी मामलों में गंभीरता से जांच की जा रही है। अलग-अलग टीमों का गठन कर आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। लगातार हो रही इन घटनाओं से भिवंडी में डर का माहौल है। परिजन अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वहीं पुलिस पर जल्द से जल्द इन मामलों का खुलासा करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

नशे के सौदागरों पर करारा वार, तीन ठिकानों पर पुलिस का एक्शन

खुलेआम नशा करते आरोपी दबोचे गए, शहर में ड्रग्स नेटवर्क पर सख्ती तेज, 25 हजार का गांजा जब्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत शांतीनगर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ड्रग्स के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में तीन मामलों का खुलासा हुआ, जहां गांजा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहली कार्रवाई में पुलिस ने गणेश मेडिकल के सामने छापा मारकर फिरोज वारिक हुसैन खान (45) को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 25 हजार रुपये कीमत का 1.46 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी को 26 मार्च 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरे मामले में पुलिस ने कमलेश जगदीश सरोज (32) को भादवड नाका के पास शगुन मैरेज हॉल के सामने सार्वजनिक स्थान पर गांजा सेवन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इस तरह खुलेआम नशा करने से इलाके में गलत संदेश जा रहा था, जिसे देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।तीसरी कार्रवाई भारत कंपाउंड क्षेत्र में की गई, जहां नजरुद्दीन सिद्दीकी (22) को संदिग्ध हालत में हिरासत में लिया गया। पूछताछ और जांच में सामने आया कि वह भी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा था। तीनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सुत्रों के अनुसार यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और शहर में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान और तेज किया जाएगा। पुलिस ने साफ किया है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

बंद घर का ताला तोड़कर चोरी, 2.6 लाख रुपये के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। निजामपुरा थाना क्षेत्र में बंद घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख 60 हजार रुपये के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता शांतिलाल साकलचंद जैन (68) गोकुल नगर, भिवंडी में रहते हैं और कपड़ा व्यापार से जुड़े हैं। घटना 27 मार्च की शाम करीब 7:25 बजे से 8:55 बजे के बीच की बताई गई है। शिकायत में कहा गया है कि उस समय घर में उनकी पत्नी और बेटी मौजूद नहीं थीं और वे पास के जैन मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम के लिए गई थीं। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बेडरूम में रखी अलमारी का लॉकर तोड़ दिया। चोरों ने लॉकर में रखी नकदी के साथ सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। निजामपुरा पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

जुए के अड्डे पर पुलिस का धावा, रातों-रात बिखरा खेल

खाड़ीपार में चल रहा था संगठित जुआ रैकेट, दस आरोपी दबोचे गए, नकदी और सामग्री जब्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसते हुए निजामपुरा पुलिस ने खाड़ीपार इलाके में चल रहे जुए के अड्डे पर जोरदार छापा मारकर पूरे रैकेट को तहस-नहस कर दिया। 27 मार्च 2026 की शाम करीब साढ़े चार बजे समीर सर्विस सेंटर के पास की गई इस कार्रवाई में दस आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में लंबे समय से संगठित तरीके से जुआ खेला जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से 10570 रुपये नकद और जुए में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मजदूर, पेंटर और छोटे-मोटे काम करने वाले लोग शामिल हैं, जो अतिरिक्त कमाई के लालच में इस अवैध धंधे से जुड़े हुए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सुत्रों का कहना है कि यह केवल एक अड्डे का खुलासा नहीं, बल्कि शहर में फैल रहे जुए के नेटवर्क पर सीधा प्रहार है। अब जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि इस रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इसमें किसी बड़े गिरोह का हाथ है। निजामपुरा पुलिस ने साफ किया है कि शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे धंधों में लिप्त लोगों को किसी भी सूरत में नहीं जाएगा।

पति-पत्नी और वो पर हाई कोर्ट ने सुना दिया गजब का फैसला, पुलिस देगी सिक्योरिटी

नई दिल्ली। किसी शादीशुदा आदमी का किसी एडल्ट महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लिविंग कपल की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। यह एक ऐसा कपल है जिसमें मेल पार्टनर पहले से शादीशुदा है। कपल का कहना है कि महिला के परिवार से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन्हें ऑनर किलिंग का डर है। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से सिक्योरिटी की मांग की थी। जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत का काम कानून के अनुसार फैसला देना है ना कि सामाजिक या पारिवारिक नैतिकता के आधार पर। अगर कोई काम कानून के चलते अपराध नहीं है तो सिर्फ समाज की सोच के कारण कोर्ट उसे गलत नहीं ठहरा सकता। आज तक से जुड़े पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा मामला शाहजहांपुर के जयतीपुर थाने का है। जहां 8 जनवरी 2026 को महिला की मां ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। मां का आरोप था कि नेत्रपाल नाम का एक शख्स उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है और इसमें धर्मपाल नाम के एक और आदमी ने उसकी मदद की है।

मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर

भिवंडी में गोकशी का गोरखधंधा बेनकाब, 100 किलो प्रतिबंधित मांस जब्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में अवैध मांस कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए निजामपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु के मांस की बिक्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 100 किलो संदिग्ध मांस जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये बताई जा रही है। हालांकि, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ नहीं लग सका और मौके से फरार हो गया। यह कार्रवाई 27 मार्च की सुबह करीब 8:10 बजे कसाईवाड़ा इलाके में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां एक दुकान के जरिए प्रतिबंधित गोवंश का मांस खुलेआम बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही टीम ने महिला सार्वजनिक शौचालय के पास स्थित दुकान पर छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में मांस बरामद किया। जांच में आरोपी की पहचान शहबाज उर्फ कान्हया शफीउद्दीन अंसारी (32) के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह मौके से फरार हो गया, जिसके चलते उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिसकर्मी अशोक कोदे की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राणी संरक्षण अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त किए गए मांस को जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि इसकी पुष्टि की जा सके। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस सुत्रों का कहना है कि शहर में इस तरह के अवैध धंधों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दो मासूम बच्चियों से छेड़छाड़, एक महिला से दुष्कर्म के प्रयास में केस दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शहर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में कानून के प्रावधानों के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहली घटना शांतिनगर थाना क्षेत्र की है। 28 वर्षीय महिला ने शिकायत में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था। आरोप है कि 26 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे आरोपी जबरन उसके घर में घुसा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।दूसरी घटना भिवंडी शहर क्षेत्र की है। 30 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि 27 मार्च की रात करीब 9 बजे एक युवक ने उसकी नाबालिग बच्ची और एक अन्य बच्ची के साथ अनुचित हरकत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी इरफान मशाक शेख (23) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, 2012 की संबंधित धाराओं तथा बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों मामलों की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भिवंडी में गैस के लिए जंग, आधी रात से कतार में खड़े मजदूर

5 किलो सिलेंडर की किल्लत से हालात बेकाबू, सैकड़ों लोग लाइन में फिर भी खाली हाथ लौटने को मजबूर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में ईंधन संकट अब भयावह रूप ले चुका है। 5 किलो गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने मजदूरों की जिंदगी को संघर्ष में बदल दिया है। हालात ऐसे हैं कि सिलेंडर पाने के लिए लोग आधी रात से ही गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े होने को मजबूर हैं। भिवंडी, जिसे मजदूरों का शहर कहा जाता है, यहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक खाना बनाने के लिए छोटे गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं। लेकिन आपूर्ति में भारी कमी के चलते एजेंसियों पर रोजाना केवल 40 से 50 सिलेंडर ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसके कारण 'पहले आओ-पहले पाओ' की स्थिति बन गई है। सिलेंडर के लिए मजदूर रात 12 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो अपनी बारी सुनिश्चित करने के लिए वहीं जमीन पर सोकर रात गुजारते हैं। सुबह होते-होते कतारें सैकड़ों में पहुंच जाती हैं, लेकिन सीमित स्टॉक के कारण ज्यादातर लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। पिछले कई दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। लगातार लाइन में लगने के बावजूद गैस नहीं मिलने से मजदूरों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि न तो वे रोज होटल का खाना खा सकते हैं और न ही महंगी बिजली की सिगड़ी का खर्च उठा सकते हैं, ऐसे में घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। गैस एजेंसी संचालकों का भी कहना है कि आपूर्ति बेहद सीमित हो गई है। एक एजेंसी पर 120 सिलेंडर पहुंचने के बावजूद 400 से 500 लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे सभी को गैस देना संभव नहीं हो पा रहा है। अब सिलेंडर देने से पहले आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और शपथ पत्र लिया जा रहा है, ताकि इसका गलत उपयोग न हो। बढ़ती परेशानी के बीच मजदूरों ने प्रशासन से मांग की है कि 5 किलो गैस सिलेंडर की आपूर्ति तुरंत बढ़ाई जाए। फिलहाल भिवंडी में गैस के लिए मची यह जंग आम लोगों के धैर्य की कड़ी परीक्षा ले रही हैं।

होटल ठप, चाय फीकी और घरों में चूल्हा बुझा

ईंधन संकट का विस्फोट, गैस गायब तो कोयला-लकड़ी ने तोड़ी कमर

केरोसिन से वंचित होने पर महिलाओं का फूटा गुस्सा

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर अब सीधे भिवंडी की रसोई तक पहुंच गया है। गैस की भारी किल्लत ने शहर की रफ्तार थाम दी है, जिससे आम नागरिकों से लेकर छोटे व्यापारियों तक की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है। कमर्शियल गैस की सप्लाई लगभग ठप होने से होटल, चाय स्टॉल और रेहड़ी-पटरी वाले कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गैस के अभाव में होटल व्यवसायियों को मजबूरी में कोयला और लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। अचानक बढ़ी मांग के चलते इनके दामों में 15 से 20 प्रतिशत तक उछाल आ गया है। पत्थर कोयला 25 रुपये प्रति किलो, लकड़ी का कोयला 40 रुपये और ईंधन लकड़ी 10 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जिससे कारोबारियों की लागत बढ़ गई है।

सिगड़ी पर खाना बनाना न सिर्फ मुश्किल हो गया है, बल्कि इससे खाने के स्वाद और मेनू पर भी असर पड़ा है। कई व्यंजन अब बन ही नहीं पा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को सीमित विकल्पों से ही संतोष करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर चाय प्रेमियों पर पड़ा है, जहां अब कड़क और स्पेशल चाय की जगह थर्मस में बनी साधारण चाय ही मिल रही है।

ईंधन संकट का असर घरों में भी साफ दिख रहा है। छोटे-छोटे घरों में रहने वाली महिलाओं के लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना लगभग असंभव हो गया है। गैस सिलेंडर न मिलने से रसोई ठप पड़ गई है, जिससे भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 3 लीटर केरोसिन देने की योजना में ठाणे राशनिंग विभाग को शामिल नहीं किया गया। इसका सीधा असर भिवंडी के हजारों परिवारों पर पड़ा है, जिन्हें इस राहत से वंचित रहना पड़ेगा। महिलाओं ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ा विरोध जताया है और प्रशासन से तत्काल केरोसिन उपलब्ध कराने की मांग की है। शहर में बढ़ते असंतोष के बीच अब सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है कि कब तक इस संकट से राहत मिलती है।

यूपी-112 सेवा को मिली मजबूती, चार नई पीआरवी वाहनो को एसपी ने दिखाई हरी झंडी

भदोहीः जनपद में आपातकालीन पुलिस सेवा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शनिवार को चार नई पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (पीआरवी) को हरी झंडी दिखाकर संबंधित थानों के लिए रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरपतहां से इन वाहनों को रवाना करते हुए कहा कि इससे पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

नई पीआरवी वाहनों को ज्ञानपुर, औराई, भदोही व सुरियावां थाना क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इनकी मदद से आपातकालीन कॉल पर पुलिस की पहुंच तेज होगी, जिससे अपराध नियंत्रण के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यूपी-112 सेवा पहले से ही जनता के लिए एक मजबूत सहारा है और इन नए वाहनों के जुड़ने से यह सेवा और अधिक प्रभावी व तेज बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वाहनों का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, ताकि हर जरूरतमंद को समय पर सहायता मिल सके।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक, परिवहन शाखा प्रभारी, डायल-112 प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। भदोही पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जन सुरक्षा के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे, जिससे अपराध पर अंकुश लगाने में मदद

पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले-कांग्रेस-एसपी ने यूपी के विकास को सालों तक रोका था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क में हाल ही में की गई कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और इसे राज्य भर के नागरिकों और व्यवसायों के लिए एक स्वागत योग्य राहत बताया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पिछले 11-12 वर्षों में आपने 'नए भारत' को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग अब वैश्विक विमानन मानचित्र पर देश को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, जो आपके विज़न को साकार कर रहा है... कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने अपनी अक्षमता के कारण देश और राज्य दोनों को विकास के अवरोध में डाल दिया। 2002 से 2017 तक उत्तर प्रदेश लगातार इस कलंक को झेलता रहा और इस तरह के ठहराव का शिकार रहा। हालांकि, पिछले 12 वर्षों में देश और पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने हमारी 'दोहरी इंजन सरकार' के नेतृत्व में जो तीव्र विकास देखा है, उसके कारण हम इन अवरोधों को तोड़ते हुए विश्व के सामने एक नई पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं।

मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों पर उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को ऐतिहासिक रूप से धीमा करने वाली बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नीतिगत देरी और प्रशासनिक अड़चनों ने विकास में बाधा डाली थी, और परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान केंद्र और राज्य प्रशासन की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उत्पाद शुल्क में कटौती से न केवल परिवहन लागत कम होगी, बल्कि अंतिम उपभोक्ताओं के लिए भी यह वहनीय होगा, जिससे आर्थिक गतिविधि मजबूत होगी और राज्य भर के उद्योगों को समर्थन मिलेगा। उन्होंने निर्बाध विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और इस बात पर बल दिया कि तीव्र प्रगति प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।

मनोरंजन

अक्षय ओबेरॉय वर्ष 2026 की तीन बड़ी फिल्मों का बने हिस्सा!

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय ओबेरॉय इस समय अपने करियर के एक बेहद खास दौर से गुज़र रहे हैं, जहां वह 2026 की तीन सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स - टॉक्सिक, किंग और नीरज पांडे की फिल्म का हैं। अक्षय ओबेरॉय ने कहा, 'यदि आप मुझसे दो साल पहले पूछते कि क्या मैंने ऐसा समय सोचा था, तो मैं ईमानदारी से 'नहीं' कहता। यह इंडस्ट्री आपको हर दिन विनम्र बनना सिखाती है।

मैं लंबे समय से यहां हूं, चुपचाप अपना काम करता रहा, प्रक्रिया पर भरोसा रखा, कभी-कभी खुद पर शक भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज जब मैं ऐसे मुकाम पर हूं जहां मैं टॉक्सिक, किंग और नीरज पांडे की अगली

प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं और लोग सच में उत्साहित हैं, तो यह एहसास बहुत ही खास और भावुक कर देने वाला है।'

अक्षय ओबेरॉय ने कहा, 'कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी एक पूरा चक्र पूरा कर चुकी है। फाइटर मेरे लिए सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि भावनात्मक मोड़ भी था। इसने मुझे याद दिलाया कि मैंने यह रास्ता क्यों चुना था। वहां से टॉक्सिक, फिर किंग, और अब नीरज पांडे जैसे फिल्मकार के साथ काम करना. ये वो पल हैं जिनकी एक अभिनेता खामोशी से उम्मीद करता है, लेकिन कभी उन्हें हल्के में नहीं लेता। मुझे सच में लगता है कि मुझे अब मेरा हक मिल रहा है, वो भी अचानक नहीं, बल्कि सालों की सीख, इंतज़ार और मेहनत के बाद।'

अक्षय ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, 'ऐसे भी दौर आए जब कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं लगता था, जब आप अपने फैसलों पर सवाल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वही साल आपको ऐसे पलों के लिए तैयार करते हैं। आज मैं हर मौके के लिए आभारी हूं, उन फिल्मकारों के भरोसे के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और उन दर्शकों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धीरे-धीरे मेरे काम को अपनाया। यह समय मेरे लिए बेहद भावुक है, क्योंकि यह मेरे सफर, संघर्ष और उस भरोसे को सही साबित करता है कि अच्छा काम आखिरकार अपना समय ज़रूर पाता है।'

सास-ससुर का विवाद कोर्ट में

30,000 करोड़ रुपये के कानूनी विवाद में प्रिया कपूर का बड़ा फैसला

मुंबई। पिछले साल जून में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स-हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद, उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर इस समय करिश्मा कपूर के बच्चों, सास रानी कपूर और बहन मंदिरा कपूर स्मिथ के साथ कानूनी विवाद में फंसी हुई हैं। यह विवाद 30,000 करोड़ रुपये की विरासत को लेकर है। इस बीच, RK फैमिली ट्रस्ट की ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के तौर पर काम कर रही प्रिया ने 25 मार्च, 2026 से रानी कपूर को ट्रस्टी के पद से हटाने के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है।

24 मार्च, 2026 को जारी किया गया यह नोटिस ट्रस्ट के कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद के बैकग्राउंड में जारी किया गया है। यह कदम रानी कपूर द्वारा प्रिया को उनके पद से हटाने की कोशिश के बाद उठाया गया है, जिससे दिवंगत संजय कपूर के बड़े बिजनेस एम्पायर पर चल रहा विवाद और बढ़ गया है।

रानी कपूर के कामों पर चिंता

इस जानकारी के मुताबिक, 'ख फैमिली ट्रस्ट 2017 में एक प्राइवेट और इर्रिवोकेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया था, जिसमें दिवंगत संजय कपूर अकेले बेनिफिशियरी थे। जून 2025 में उनकी मौत के बाद, ट्रस्ट में बेनिफिशियल राइट्स उनके बच्चों मास्टर अजारियास सूरी कपूर, समायरा कपूर और मास्टर कियान कपूर को ट्रांसफर कर दिए गए। नोटिस में रानी कपूर द्वारा कथित तौर पर एकमात्र बेनिफिशियरी की मौत के बाद किए गए कुछ कामों पर चिंता जताई गई है। इसमें जनवरी 2026 में जारी किए गए प्रोटेस्ट नोटिस का भी ज़िक्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें ट्रस्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है और उसके एसेट्स से राहत मांगी गई है।

प्रिया ने लेटर में क्या कहा?

अपने लेटर में, प्रिया सचदेव कपूर ने कहा है कि ये काम ट्रस्ट डीड की शर्तों के खिलाफ हैं और इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के प्रोविज़न का उल्लंघन करते हैं और बेनिफिशियरी के हितों के लिए भी नुकसानदायक हैं। ट्रस्ट डीड के सेक्शन 8.11 का हवाला देते हुए, उन्होंने रानी कपूर को ट्रस्टी के पद से फॉर्मली हटाने के लिए एक नोटिस दिया है। इस नोटिस में साफ किया गया है कि 25 मार्च, 2026 के बाद, रानी कपूर के पास ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स या ट्रांज़ैक्शन से डील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि इस तारीख के बाद ट्रस्ट के नाम पर किया गया कोई भी काम इनवैलिड माना जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने पर लीगल एक्शन लिया जाएगा।

सास और बहू का कोर्ट में झगड़ा

यह सब सास और बहू के बीच बढ़ते झगड़े के बैकग्राउंड में सामने आया है। यह भी पता चला है कि रानी कपूर ने ट्रस्ट को लेकर कई कदम उठाए हैं, जिससे प्रिया सचदेव कपूर की पोजीशन पर असर पड़ा है।

मिस्टर एंड मिसेज परशुराम में आया बड़ा मोड़! हुई खालिद सिद्दीकी की एंट्री , सबसे बड़े विलेन के तौर पर सबको चौंकाएंगे खालिद

मुंबई। अभिनेता खालिद सिद्दीकी से स्टार प्लस के शो 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' में एंट्री कर रहे हैं। स्टार प्लस के शो 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' में नील भट्ट शिवप्रसाद और परशुराम के चुनौतीपूर्ण डबल रोल में नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी शालिनी का किरदार शांभवी सिंह निभा रही हैं, जो अपने पति की स्पाई वाली छुपी जिंदगी से अनजान है। इस दिलचस्प कहानी के बीच अब एक नए किरदार की एंट्री होने जा रही है, जो एक बड़ा मोड़ लेकर आएगी और सबसे बड़े विलेन के तौर पर सबको चौंका देगी।

खालिद सिद्दीकी करण कुलकर्णी के रूप में शो में एंट्री कर रहे हैं, जो कहानी में हलचल मचाने वाला खतरनाक एंटागोनिस्ट है। करण शालिनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला है और उसकी मौजूदगी से रहस्य और खतरे का माहौल बन जाएगा, जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है। करण कुलकर्णी, कबीर कुलकर्णी का पिता है, वही कबीर जिसने शालिनी के बच्चों के किडनैपिंग के पीछे हाथ था। उसकी एंट्री शालिनी की जिंदगी को हिला कर रख देगी, जिससे ड्रामा और खतरा दोनों बढ़ जाएंगे और उसके परिवार पर एक गहरा साया छा जाएगा।

खालिद सिद्दीकी ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं करण कुलकर्णी का रोल निभा रहा हूं, जो कबीर का पिता है। करण अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यही वजह है कि उसका देशमुख परिवार से टकराव होता है। उसमें नेगेटिव ट्रेट्स हैं और वह पूरी तरह पितृ मोह में बंधा हुआ है।'

खालिद सिद्दीकी ने शो की कास्ट के साथ काम करने के अनुभव पर कहा, 'यह बहुत ही प्यारी टीम है, सभी काफी सपोर्टिव और वेलकमिंग हैं, इस टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए खुशी की बात है।'उन्होंने अपने फैंस के लिए भी एक संदेश दिया, 'मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि शो को खूब प्यार दें और इसे हर दिन रात 8:30 बजे जरूर देखें।' स्टार प्लस के साथ अपने जुड़ाव पर उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं स्टार प्लस का इन-हाउस एक्टर हूं, क्योंकि मैंने अपने करियर में ज्यादातर शो इसी चैनल के लिए किए हैं। यहां काम करना हमेशा घर जैसा लगता है। 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' हर दिन रात 8:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर प्रसारित होता है।

आईपीएल का दमदार आगाजः पहले ही मैच में पार हुआ 200 रनों का आंकड़ा, ईशान ने कायम रखी फॉर्म; अनिकेत ने दिखाया दम

बंगलूरू। आईपीएल 2026 का दमदार आगाज हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ पहले ही मैच में 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। सीजन के पहले ही मैच में टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया है। सनराइजर्स के लिए इस मैच में स्टैंड इन कप्तान ईशान किशन ने दमदार प्रदर्शन किया। ईशान ने टी20 विश्व कप की फॉर्म को आईपीएल में भी बरकरार रखा है।

पहले ही मुकाबले में हैदराबाद ने ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में नौ विकेट पर 201 रन बनाए हैं। आरसीबी के लिए जैकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा को एक-एक सफलता मिली।

सनराइजर्स की खराब शुरुआत

ईशान ने आरसीबी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक लगाया। ईशान हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप में भी अच्छी फॉर्म में थे और उन्होंने भारत के लिए यादगार पारियां खेली थी। ईशान ने ऐसा ही कुछ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किया। आरसीबी ने टॉस जीतकर सनराइजर्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। जैकब डफी ने सनराइजर्स को शुरुआती झटके दिए और पहले तीन विकेट अपने नाम करने में सफल रहे। टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने छक्के के साथ खाता खोला था, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और सात रन बनाकर आउट हुए। टी20 क्रिकेट में यह 16वीं बार और आईपीएल में पांचवीं बार था जब अभिषेक ने छक्के के साथ खाता खोला।

ईशान ने पूरे किए तीन हजार रन

खराब शुरुआत के बाद ईशान ने सनराइजर्स की पारी को संभाला। उन्होंने ना सिर्फ सनराइजर्स की पारी आगे बढ़ाई, बल्कि रन गति भी धीमी नहीं पड़ने दी। ईशान ने इस दौरान आईपीएल में तीन हजार रन भी पूरे कर लिए। यह लगातार दूसरा आईपीएल सीजन है जब ईशान ने सनराइजर्स के लिए पहले मैच में दमदार बल्लेबाजी की। इससे पहले ईशान ने पिछले सीजन सनराइजर्स के पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 47 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए थे। वहीं, आरसीबी के खिलाफ मैच में ईशान ने 38 गेंदों पर आठ चौकों और पांच छक्कों की मदद से 80 रन बनाए। उनके अलावा अनिकेत वर्मा ने भी प्रभावित किया जिन्होंने 18 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। वहीं, हेनरिक क्लासेन 22 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। सनराइजर्स के लिए ईशान, अनिकेत और क्लासेन के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका।

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका, धोनी हुए चोटिल; सीएसके के शुरुआती कितने मैचों में नहीं खेलेंगे?

चेन्नई। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी चोट के कारण शुरुआती चार मुकाबलों से बाहर हो सकते हैं। सीएसके ने अपने आधिकारिक बयान में जानकारी दी कि धोनी इस समय काफ स्ट्रेन (पिंडली की चोट) से जूझ रहे हैं और फिलहाल रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) से गुजर रहे हैं। टीम के बयान के मुताबिक, 'एमएस धोनी इस समय काफ स्ट्रेन से उबरने की प्रक्रिया में हैं। इसके चलते वह आईपीएल के पहले दो हफ्तों से बाहर रह सकते हैं।'

क्या है चोट और कितने मैच मिस करेंगे?

धोनी की यह चोट मांसपेशियों से जुड़ी है, जिसे ठीक होने में समय लगता है। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि वह पहले दो हफ्ते नहीं खेलेंगे यानी सीएसके के शुरुआती तीन से चार मैच मिस कर सकते हैं। यह टीम के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि धोनी अनुभव और नेतृत्व दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं। सीएसके को शुरुआती दो हफ्तों में 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स से गुवाहाटी में, तीन अप्रैल को पंजाब किंग्स से चेन्नई में, पांच अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से बंगलूरू में और 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से चेन्नई में खेलना है। इसके बाद 14 अप्रैल को सीएसके का मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स से चेन्नई में होगा। धोनी दिल्ली के खिलाफ या फिर कोलकाता के खिलाफ मैच में वापसी कर सकते हैं।

सीएसके के लिए क्यों बड़ा नुकसान?

धोनी भले ही अब कप्तान नहीं हैं, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम के लिए बेहद अहम रहती है। वह अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर टीम से जुड़े हुए हैं। विकेटकीपिंग में अनुभव, डेथ ओवर में फिनिशिंग और युवा खिलाड़ियों को गाइड करना, इन सभी मामलों में उनकी कमी साफ महसूस होगी। 44 वर्षीय एमएस धोनी के आईपीएल भविष्य को लेकर हर सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के अभियान के बाद जोरदार चर्चा शुरू हो जाती है।

चूंकि धोनी अब सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं, इसलिए उनके लिए मैच फिटनेस बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। पिछले आईपीएल सीजन में धोनी ने 14 मैच खेले थे और निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम की पारी को आखिरी ओवरों में तेज फिनिश देने का काम किया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद से वह लगातार घुटने की समस्या से जूझते रहे हैं। इसी कारण उन्होंने 2023 में सर्जरी भी कराई थी।

किसे मिल सकता है मौका?

धोनी की गैरमौजूदगी में सीएसके मैनेजमेंट को प्लेइंग-11 में बदलाव करना पड़ेगा। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी किसी अन्य खिलाड़ी को मिल सकती है। धोनी के अलावा विकेटकीपिंग के लिए टीम के पास तीन अन्य विकल्प भी हैं। इनमें संजू सैमसन, उर्विल पटेल और कार्तिक शर्मा शामिल हैं। संजू का खेलना तय है। अब उर्विल और कार्तिक दोनों को प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है। ऐसे में विकेटकीपिंग का दारोमदार किस पर होगा, यह देखने वाली बात होगी। मिडिल ऑर्डर में भी फेरबदल संभव है।

स्मृति मंधाना के साथ आईपीएल का मुकाबला देखने पहुंचीं अनुष्का शर्मा

बंगलूरू। आईपीएल के 19वें संस्करण का आगाज बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जोरदार अंदाज में हुआ है, जहां गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने हैं। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां भी स्टेडियम पहुंचीं।

मंधाना और अनुष्का की मौजूदगी

मैच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अनुष्का शर्मा की मौजूदगी की रही, जो अपने पति विराट कोहली की टीम आरसीबी को सपोर्ट करने स्टेडियम में नजर आईं। उनके साथ आरसीबी महिला टीम की स्टार कप्तान स्मृति मंधाना भी मौजूद थीं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

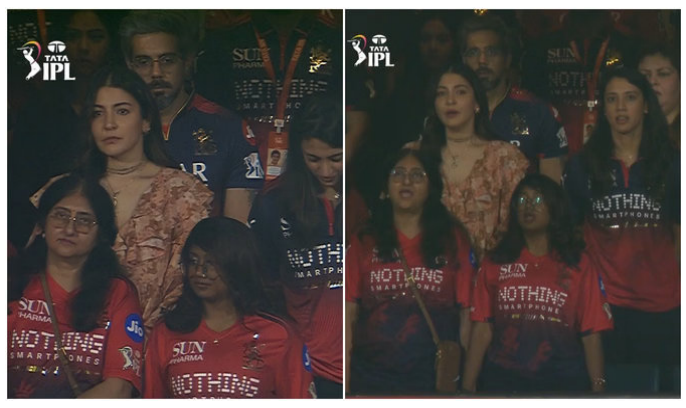

फैंस में उत्साह

मैच की बात करें तो आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रजत पाटीदार ने नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरते हुए दो नए खिलाड़ियों जैकब डफी और अभिनंदन सिंह को डेब्यू का मौका दिया है। सीजन के पहले मुकाबले में जहां एक ओर मैदान पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं स्टैंड्स में मौजूद सितारों की मौजूदगी ने इस मैच के रोमांच को और भी बढ़ा दिया है। अनुष्का शर्मा और स्मृति मंधाना की मौजूदगी ने आरसीबी फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है।

मुंबई इंडियंस के कोच जयवर्धने ने हार्दिक को सराहा, बताया बेहतरीन ऑलराउंडर; सुधार पर कही ये बात

मुंबई। मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच माहेला जयवर्धने ने कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी और खेल में हुए सुधार की जमकर तारीफ की है। आईपीएल 2026 में मुंबई अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मुंबई में होने वाले मुकाबले से करेगी।

हार्दिक से पहली मुलाकात का किया जिक्र

जयवर्धने ने कहा, मैं हार्दिक से पहली बार 2017 में मिला था। वह युवा थे लेकिन उनमें प्रतिभा और बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। यही बात मुझे हार्दिक में हमेशा से पसंद आई है। आज भी खेल के प्रति उनकी ऊर्जा वैसी ही है। उन्हें क्रिकेट के खेल से बहुत अधिक लगाव है और वह इसके बारे में बहुत बातें करते हैं। मैं आठ साल से मुंबई इंडियंस के साथ हूं और एक लीडर के तौर पर उनका विकास, मैदान पर उनकी समझदारी और जिस तरह से वह बेहतर हुए हैं शायद सीमित ओवर के खेल के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं। अपने करियर के दौरान चोटों और वर्कलोड की वजह से पांड्या को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन पर बात करते हुए जयवर्धने ने कहा, हार्दिक को जो चोटें लगीं उससे उनके शरीर पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे थे। काम के

बोझ को मैनेज करने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। अब वह इस बात को समझते हैं और हमारे पास उनके काम के बोझ को संभालने का एक तय तरीका है। जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के उस अहम पड़ाव पर पहुंच जाता है तो उसके वर्कलोड को मैनेज करना जरूरी होता है।

आलोचकों पर भड़के मिचेल स्टार्क, बताया आईपीएल के शुरुआती चरण से बाहर होने का कारण; डीसी से मांगी माफी

नई दिल्ली ।मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2026 से शुरुआती गैरमौजूदगी पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह कोहनी और कंधे की चोट से उबर रहे हैं, न कि कमिटमेंट की कमी है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और फैंस से माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया कि फिट होते ही जल्द टीम से जुड़ेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों से अपनी गैरमौजूदगी को लेकर हो रही आलोचनाओं पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया कि वह किसी लापरवाही या कमिटमेंट की कमी के कारण नहीं, बल्कि चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं। इससे पहले शुक्रवार को स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली ने भी सोशल मीडिया पर तेज गेंदबाज की अनुपलब्धता को लेकर जानकारी दी थी।

क्या है पूरा मामला

स्टार्क अभी तक दिल्ली कैपिटल्स से नहीं जुड़े हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ गई। भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर सहित कई लोगों ने विदेशी खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए थे। स्टार्क ने खुद सामने आकर बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई समर के दौरान कोहनी और कंधे में चोट लगी थी, जिसकी गंभीरता उन्हें शुरुआत में पता नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल रिहैब और रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस कार्य प्रबंधन के चलते आईपीएल के शुरुआती चरण से बाहर रहेंगे।

आलोचकों को दिया जवाब

स्टार्क ने मीडिया में चल रही खबरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग अधूरी और गलत जानकारी के आधार पर बयान दे रहे हैं और ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उन्हें उनके शरीर की स्थिति ज्यादा पता हो।

दिल्ली कैपिटल्स और फैंस से मांगी माफी

स्टार्क ने दिल्ली कैपिटल्स और फैंस से माफी भी मांगी। उन्होंने माना कि उनकी गैरमौजूदगी टीम के लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह जल्द से जल्द टीम से जुड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अपनी पत्नियों के कारण खिलाड़ी लेते हैं संन्यास.., योगराज सिंह का विवादित बयान

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर अपने अजीबो-गरीब बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये बयान खिलाड़ियों की पत्नियों को लेकर दिया है जिससे वो आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। योगराज ने साफ कहा कि उम्र को खिलाड़ी के प्रदर्शन से जोड़ना गलत है। उनके मुताबिक फिटनेस और प्रदर्शन ही किसी खिलाड़ी के करियर का असली पैमाना होना चाहिए, ना कि उम्र। इनसाइड स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में योगराज सिंह ने कहा कि, भारत में लोग 40 की उम्र के बाद खुद को बूढ़ा मानने लगते हैं, महिलाएं 30 के बाद कहती हैं कि अब हम फिट नहीं रह सकते, बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन खेल को उम्र से जोड़ना बिल्कुल गलत है। योगराज सिंह ने कहा कि, अक्सर घर की महिलाएं, पत्नियां आपको समझाने लगती हैं कि अब रिटायर हो जाओ, परिवार और बच्चों पर ध्यान दो। मेरा मानना है कि महिलाओं को खिलाड़ी और उसके करियर के बीच नहीं आना चाहिए। एक खिलाड़ी और एक फकीर का कोई धर्म या वर्ग नहीं होता, वे भगवान के होते हैं।

पश्चिम रेलवे

संकेत एवं दूरसंचार कार्य

वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (उत्तर), मुंबई सेंट्रल, द्वितीय तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008 द्वारा ई-निविदा संख्या एसजी_216_2_156_डब्ल्यूए दिनांक 23/03/2026 आमंत्रित की जाती है। **कार्य एवं स्थानः** मुंबई मंडल के विरार-सूरत खंड में निम्नलिखित कार्यों के संबंध में संकेत एवं दूरसंचार कार्यः**(1)** विरार-सूरत - टीटीआर (टीडब्ल्यूएस + डब्ल्यूसीएमएस) 87 संख्या एवं टीएसईजे 56 संख्या **(2)** जोरावासन-सूरत (डाउन) - टीआरआर (पी) - 8.702 ट्रैक किलोमीटर **(3)** विरार-जोरावासन - सीटीआर (पी) - 0.632 ट्रैक किलोमीटर, टीआरआर (पी) - 4.146 ट्रैक किलोमीटर एवं टीएसआर (पी) - 3.404 ट्रैक किलोमीटर। **कार्य की अनुमानित लागतः** 1,24,31,262.39 रुपये। **बयाना राशिः** 2,48,700 रुपये। **ई-निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समयः** 21.04.2026 को 15:00 बजे तक। **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** 21.04.2026 को 15:30 बजे। निविदा को वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है। 1254

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

नॉन फेयर रेवन्यू (NFR) के माध्यम से ई–नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक–रतलाम मंडल– पश्चिम रेलवे ने नॉन फेयर रेवन्यू (NFR) के माध्यम से ई–नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को www.ireps.gov.in के (ई–ऑक्शन लीजिंग) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। **केटलॉग सं.**– MSS-RTM-63. **अनुबंध का प्रकार** : Non Fare Revenue (NFR). **लॉट न.** : MSS-RTM-INDB-GBTPA-80-26-2, (Misc.-Static-Services - Glow ball tower with Promotional Audio), **अनुबंध की अवधि** : 05 Years. ई–नीलामी की तिथि और समय लॉट के लिए ई–नीलामी **दिनांक 11.04.2026 को 12:00 बजे प्रारंभ होगी।** प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। **IREPS** के ई–ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

SNP-524

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

बेंगलुरु विश्वविद्यालय में विवादः छात्र को 'आतंकवादी' कहने वाले प्राध्यापक निलंबित, छात्र संगठन ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

बेंगलुरु। बेंगलुरु के एक कॉलेज में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब एक प्रोफेसर को कक्षा में एक मुस्लिम छात्र पर कथित तौर पर चिल्लाते हुए और उसे 'आतंकवादी' कहते हुए कैमरे में कैद किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है। खबरों के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को शहर के पीईएस विश्वविद्यालय में हुई। छात्र, जिसकी पहचान अफ्फान के रूप में हुई है, ने किसी से मिलने के लिए प्रोफेसर से कक्षा से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और कक्षा के वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार, प्रोफेसर डॉ. मुरलीधर देशपांडे ने कथित तौर पर छात्र के प्रति आक्रामक प्रतिक्रिया दी और दूसरों के सामने उसे 'आतंकवादी' कहा। वीडियो में, जिसमें काफी शोरगुल है, प्रोफेसर को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, 'शर्म नहीं आती, तुमको।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत शांत रहूंगा,' और फिर कथित तौर पर 'आतंकवादी' शब्द दोहराया। उन पर कई अपशब्द कहने का भी आरोप है, जिनमें ईरान युद्ध के लिए 'अपने जैसे लोगों' को दोषी ठहराना, यह कहना कि डोनाल्ड ट्रम्प 'आएंगे और उसे ले जाएंगे', और छात्र को 'नरक में जाने' की धमकी देना शामिल है।

पूरी घटना कक्षा में मौजूद एक अन्य छात्र ने रिकॉर्ड कर ली। जनता के भारी विरोध के बाद, विश्वविद्यालय ने जांच लंबित रहने तक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कथित घटना के तीन दिन बाद की गई। बताया कि प्रोफेसर की टिप्पणियों का विरोध करने वाले छात्र का समर्थन करने वाले तीन छात्रों को भी अन्य कारणों से निलंबित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि छात्र की शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की विस्तृत जांच लंबित रहने तक, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित रखा जाता है। हालांकि, आरोपों की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया है। इस घटना से मचे बवाल के बाद, कांग्रेस के छात्र संगठन - नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। इस घटनाक्रम ने ऑनलाइन भी व्यापक आक्रोश पैदा किया, जिसमें कई लोगों ने सांप्रदायिक टिप्पणी की निंदा करते हुए प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप से आंगनवाड़ी केंद्र नए भवन में शिफ्ट, बच्चों को मिला सुरक्षित वातावरण

गुना। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले की ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा अंतर्गत ग्राम मामला में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति पर त्वरित संज्ञान लेते हुए बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया। उनके निर्देशों के बाद आंगनवाड़ी केंद्र को सुरक्षित नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है।

तत्काल संज्ञान और कड़े निर्देश

ग्राम में आंगनवाड़ी केंद्र लंबे समय से एक पुराने और जर्जर भवन में संचालित हो रहा था। मामले की जानकारी प्राप्त होते ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित की जाएं।

प्रशासन हरकत में, केंद्र स्थानांतरित

केंद्रीय मंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए आंगनवाड़ी केंद्र को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे लाभार्थियों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके।

जनसुरक्षा सर्वोपरि, लापरवाही पर सख्त रुख

केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि जनसुरक्षा सर्वोपरि है और इस प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाए।

पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत, ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की कड़ी निंदा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की और क्षेत्र की ऊर्जा अवसंरचना पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों का विरोध करता है और इसे गंभीर चिंता का विषय मानता है।

इस दौरान दोनों नेताओं ने नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित तथा खुला रखने की आवश्यकता पर सहमति जताई। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम मार्गों की सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर अत्यंत आवश्यक बताया गया।

प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए वहां के नेतृत्व द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।

यह बातचीत हाल के समय में विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की लगातार हो रही वार्ताओं की श्रृंखला का हिस्सा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति स्थापित करने के पक्ष में है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संवाद के माध्यम से क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर कई देशों पर पड़ रहा है, जिससे खाद्य पदार्थ, ईंधन और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है और देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

भारत के टैंकर हैं, आने दो...ईरान ने दोस्त के लिए होर्मुज का रास्ता खोला

नई दिल्ली। ईरान द्वारा भारत और चार अन्य 'मित्र देशों' को संघर्ष के बीच अपने जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दिए जाने की घोषणा के बाद, भारत जा रहे दो और एलपीजी टैंकर शनिवार को संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे। नवीनतम शिपिंग आंकड़ों से पता चला है कि टैंकर, बीडब्ल्यू ईएलएम और बीडब्ल्यू टीवाईआर, उच्च जोखिम वाले गलियारे से गुजरे, जो युद्ध की शुरुआत से ही प्रभावी रूप से बंद है, और अब ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। 90,000 टन से अधिक एलपीजी (खाना पकाने की गैस) ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले दो टैंकर खाड़ी से निकलते समय लगभग 27 किमी/घंटा की गति से एक-दूसरे के करीब से गुजरे। लगभग पांच और भारतीय टैंकर, जिनमें मुख्य रूप से कच्चा तेल भरा है, अभी भी संयुक्त अरब अमीरात के निकट जलक्षेत्र में लंगर डाले हुए हैं और जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वैश्विक तेल परिवहन का पांचवां हिस्सा गुजरता है।

कुल मिलाकर, 20 भारतीय ध्वज

वाले जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने क्षेत्र में फंसे खाली जहाजों में भी एलपीजी भर रहा है। यह घटनाक्रम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची द्वारा विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्गों में से एक, होर्मुज पर तेहरान का रुख स्पष्ट करने के एक दिन बाद सामने आया है। अराघची ने सरकारी टीवी को बताया कि पांच मित्र देशों चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के टैंकरों को सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के शत्रु देशों से जुड़े जहाजों को नाकाबंदी का सामना करना जारी रहेगा। एक महीने पहले युद्ध शुरू होने के बाद से, कम से कम चार भारतीय ध्वज वाले जहाज - जग वसंत, पाइन गैस, शिवालिक और नंदा देवी - जलडमरूमध्य से गुजरे हैं।

जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि जग वसंत और पाइन गैस, जो 90,000 टन से अधिक एलपीजी ले जा रहे थे, ने अरब सागर में छोटे मार्ग से जाने के बजाय ईरान के लारक और केशम द्वीपों के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने का असामान्य मार्ग अपनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा ईरानी अधिकारियों को अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए किया गया होगा। फिर भी, भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए ईरान से मंजूरी मिलना नई दिल्ली के लिए बड़ी राहत की बात है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 90इ आयात करती है।

थक चुके हैं...अब जंग नहीं लड़ेगी इजरायल की सेना? सैन्य चीफ की लीक हुई चिट्ठी ने मचाया हड़कंप

ईरान से जंग, लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले और गाजा में हमास से दो-दो हाथ.... तीन मोर्चों पर उलझे इस्राइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने चेताया है कि जवानों की भारी मी है और इसका हल नहीं निकला तो इस्राइली सेना अंदरूनी तौर पर 'ढह' सकती है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में जनरल जमीर ने 10 खतरों (10 रेड फ्लैग) को सामने रखा। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक डिफेंस चीफ ने कहा कि अगर मैन पावर की शॉर्टेज का सॉल्यूशन नहीं निकला तो आर्मी कोलैप्स कर जाएगी। आईडीएफ के सूत्रों ने बताया कि अभी तो युद्ध चल रहा है पर इजराइल को शांति के समय गजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक के बॉर्डर्स पर सैनिकों की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सरकार सैनिकों की भर्ती नहीं करती है तो कई जगह बिग गैप्स यानी कि सैनिकों की भारी कमी हो जाएगी। आगे यह भी बताया कि सरकार की ओर से हरेदी यहूदी को सेना में शामिल करने के लिए अभी तक कोई ठोस कानून नहीं लाया गया है।

इजरायली सेना के प्रमुख ने जिन खतरों को गिनाया, उनमें जवानों की कमी के साथ मिशन पर जुटे सैनिकों पर बढ़ता बोझ, थकान, अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव, हथियार सप्लाई में कमी का जोखिम, अग्रिम मोर्चों पर अनुभवी कमांडरों की कमी और भर्ती में असमानता, ट्रेनिंग में गिरावट, मानसिक स्वास्थ्य का संकट अहम हैं। इन खतरों से जल्द नहीं निपटे तो सेना ढह जाएगी। हरेदी यहूदियों को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी कहा जाता है। मतलब इजराइल के कट्टरपंथी यहूदी। इस समुदाय के पुरुषों को तोराती उमुनातो व्यवस्था के तहत एक विशेष छूट मिलती है कि वह यहूदी धर्म ग्रंथ तोराह की पढ़ाई अपने धार्मिक स्थल पर रहकर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मिलिट्री सर्विस से छूट मिल सकती है। फिलहाल इजराइल गजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक के फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। साथ ही हरेदी यहूदियों की सेना में शामिल ना होने की वजह से सेना में भारी कमी आई है। हरेदी सेना मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी भर्ती से जुड़े बिल को वॉर की वजह से साइड कर दिया गया है क्योंकि इससे देश की एकता पर खतरा पड़ सकता है।

विपक्ष ने कहा, बिना देरी लागू हो अनिवार्य सैन्य सेवा कानून

सेना का संकट सामने आने के बाद इस्राइल के विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जवान बढ़ाने के लिए तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाए। विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि तुरंत अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू हो। सूत्रों ने बताया कि सैनिकों की कमी की बड़ी वजह यह भी है कि हरेदी समुदाय ने सेना में शामिल होने का विरोध किया है। इसके कारण अनिवार्य सैन्य सेवा कानून पर पेंच फंसा है। हरेदी समुदाय पूरा समय पवित्र यहूदी ग्रंथों की स्टडी में समर्पित रहते हैं और इन्हें सेना में काम में छूट है।

भारत का 5000 टन डीजल पहुंचा बांग्लादेश, गदगद हुए तारिक रहमान

ढाका।मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर साफ दिखाई देने लगा है। जहां ग्लोबल ऑयल सप्लाई में आई रुकावटों के चलते दुनिया के कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई और इस समय भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है और ऐसे मुश्किल हालात में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत ने आगे बढ़कर कदम उठाया। दरअसल खबर सामने आई है कि भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति भेजी है। इसके साथ ही हाल के दिनों में भारत से बांग्लादेश को कुल 15,000 टन डीजल पहुंचाया जा चुका है। बांग्लादेश को जा रही आपूर्ति आसाम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए की जा रही है जो सीधे बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाती है।

सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से यह आपूर्ति यहीं नहीं रुकने वाली बल्कि 28 मार्च को भी 6000 टन और डीजल भेजा जाएगा। वहीं अप्रैल महीने के लिए भारत ने 400 टन डीजल सप्लाई करने का प्रस्ताव बांग्लादेश को दिया जिसे बांग्लादेश ने मंजूर कर लिया है। माना जा रहा है कि इससे बांग्लादेश के बिजली उत्पादन और परिवहन व्यवस्था पर पड़े भारी दबाव को काफी हद तक कम किया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की सालाना डीजल मांग लगभग 40 लाख टन है और यह पूरी तरह आयात पर निर्भर है। ऐसे में वैश्विक संकट का सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर और आम जनजीवन पर पड़ा है। अब भारत की ओर से लिए गए इस कदम के कई अहम मायने सामने आ रहे हैं। जहां साल 2024 में बांग्लादेश में आए राजनीतिक बदलाव के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बेहद खराब दौर से गुजरना पड़ा है।

दोनों देशों के बीच कई ऊर्जा समझौतों की समीक्षा कर दी गई थी और कुछ परियोजनाएं बिल्कुल ठप पड़ गई थी। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव और सत्ता परिवर्तन के बाद वापस से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नई सरकार के साथ भारत के संबंध में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और मौजूदा डीजल की आपूर्ति को दोनों देशों के बीच फिर से मजबूत होते हुए सहयोग और भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच यह पहल ना केवल बांग्लादेश के लिए राहत की खबर है बल्कि क्षेत्ररता और सहयोग को भी मजबूत करने की एक खबर है। भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसियों की मदद करता आ रहा है और संकट की स्थिति में भारत का ये कदम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें आने वाले महीनों पर टिकी है। जहां यह देखना अहम होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच का सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। वहां की नई सरकार के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध किस दिशा में जाते हैं।

मछली पकड़ते ही पुतिन का होश उड़ा देने वाला ऐलान, बचा भारत, डरी दुनिया

रूस की मीडिया ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दिखाया है कि रूस में सर्दी खत्म होते ही तापमान थोड़ा बढ़ रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन धूप का मजा लेने के लिए मछली पकड़ने निकले हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पुतिन रूस में बढ़े थोड़े से तापमान में ऐसा फैसला ले लेंगे जो पूरी दुनिया को झुलसाने के लिए काफी है। दरअसल ईरान जंग की वजह से पेट्रोल डीजल को लेकर मची अफरातफरी के बीच खबर आई है कि रूस 4 महीनों के लिए किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए बोल भी दिया है।

सरकारी समाचार एजेंसी ने पहले बताया था कि यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। नोवाक ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण वैश्विक तेल और तेल उत्पादों के बाजार में मची उथल-पुथल से कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही, विदेशी बाजारों में रूसी ऊर्जा संसाधनों की उच्च मांग एक सकारात्मक कारक बनी हुई है। सरकार ने एक बयान में कहा कि कच्चे तेल के प्रसंस्करण की मात्रा पिछले वर्ष के स्तर पर बनी हुई है, जिससे तेल उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले तेज करने और ईंधन की मौसमी मांग में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष रूस के कई क्षेत्रों और रूसी नियंत्रण वाले यूक्रेन के कुछ हिस्सों में गैसोलीन की कमी देखी गई थी। रूस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और कमी से निपटने के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर बार-बार प्रतिबंध लगाए हैं। उद्योग सूत्रों के अनुसार, देश ने पिछले वर्ष लगभग 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल का निर्यात किया, जो लगभग 117,000 बैरल प्रति दिन के बराबर है।

रूस के इस ऐलान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इस स्थिति में भी भारत जीतता दिख रहा है। रूस ने कहा है कि हम ऐसा फैसला इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे देश में सप्लाई बनी रहे और कीमतें भी नियंत्रित रहें। आपको बता दें कि रूस के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर को पड़ेगा। मगर भारत को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वह अब आपको बताते हैं। दरअसल भारत पर असर इसलिए कम पड़ेगा क्योंकि भारत रूस से पेट्रोल नहीं बल्कि कच्चा तेल खरीदता है। ध्यान दीजिए रूस ने पेट्रोल निर्यात पर बैन लगाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है। भारत कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर निर्भर है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)